₹ 10

जुलाई 2024

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVPNO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

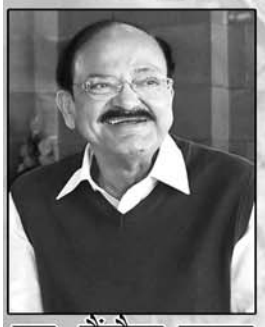

एम. वैंकैया नायडू
01 जुलाई 1949

अखिलेश यादव
01 जुलाई 1973

हरभजन सिंह
03 जुलाई 1980

स्व० रामविलास पासवान
05 जुलाई 1946

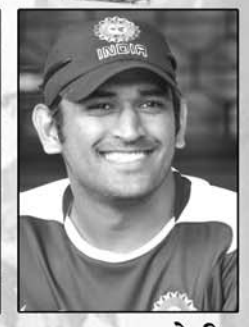

एम.एस. धोनी
07 जुलाई 1981

कैलास खेर
07 जुलाई 1973

सौरभ गांगुली
08 जुलाई 1972

सुखवीर सिंह बादल
9 जुलाई 1962

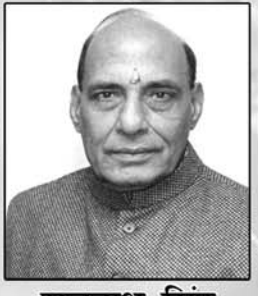

राजनाथ सिंह
10 जुलाई 1951

सुनिल गवास्कर
10 जुलाई 1949

रवि किशन
17 जुलाई 1971

प्रियंका चोपड़ा
18 जुलाई 1982

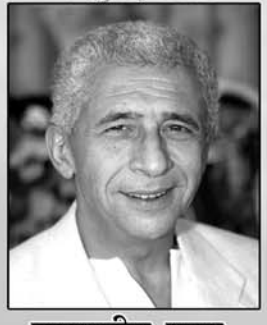

नसरूद्दीन शाह
20 जुलाई 1950

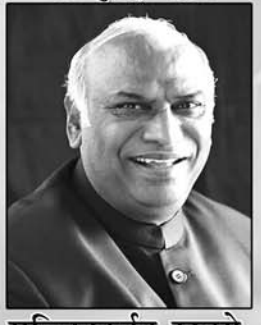

मल्लिकार्जुन खड़गे
21 जुलाई 1942

स्व० अनंत कुमार
22 जुलाई 1959

हिमेश रेशमिया
23 जुलाई 1973

पंकज आडवाणी
24 जुलाई 1985

उद्धव ठाकरे
27 जुलाई 1960

संजय दत्त
29 जुलाई 1959

सोनू निगम
30 जुलाई 1973

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

Bihar एवं Jharkhand में

महालूट

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

Education Development के नाम पर Bihar एवं Jharkhand में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर शिक्षा विभाग में जमकर महालूट किया जा रहा है। बिहार के सभी P.M.H School में टेबुल - बेंच के साथ बाउंड्री और बोरिंग - शौचालय में बड़े स्तर पर खेल किया गया है क्योंकि अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक ने विद्यालयों को व्यवस्थित करने के लिए सभी विद्यालय को काफी फंड से लैश कर दिया। ठीक इसी प्रकार Jharkhand में Computer Education के नाम पर सभी 24 जिलों में कई सौ करोड़ का घोटाला हुआ और विभाग एवं अधिकारी के संज्ञान में सबकुछ हो रहा है। विभाग में सूचीबद्ध संवेदकों को काम देने के बजाय DEO से मिलीभगत करके टेबुल - बेंच के सप्लाई का जुगाड़ चल रहा है और पूरे बिहार में इस झोल का जब पर्दाफास होने लगा तो कई जिला में जांच भी बैठा दिया गया है। IAS सिद्धार्थ ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की है लेकिन लूटेरों की गैंग पर किस हद तक कार्रवाई होगी यह देखना शेष है। Education और Health विभाग में दोनों राज्यों में भयंकर लूट मचा हुआ है। झारखंड में Computer लगा भी नहीं और उसका भुगतान वर्षो से हो रहा है और कंपनी करोड़ो रूपये पदाधिकारी से मिलकर डकार रही है। बिहार एवं झारखंड की सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी है तो दूसरी तरफ महालूट का घिनौना खेल दोनों प्रदेश में चल रहा है।

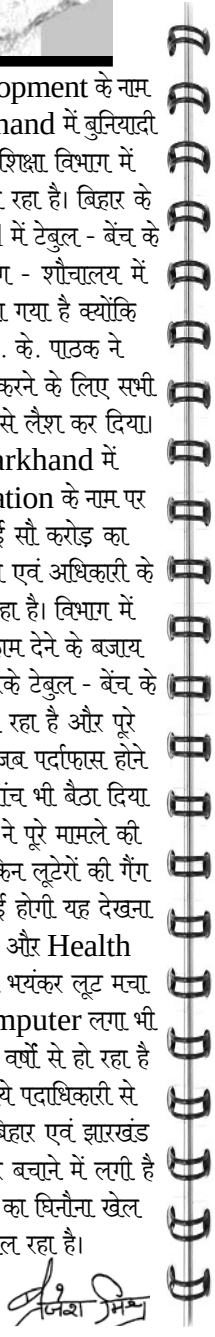

Education के नाम पर बिहार एवं झारखंड सरकार के पदाधिकारियों ने Devlopment के नाम पर संवेदकों के साथ मिलकर महालूट मचाया हुआ है और मीडिया जब इसको प्रकाशित करती है तो उसको बधाई देने के बजाय सरकार उसको कैसे परेशान करे उसका जुगाड़ लगाने में लग जाती है। दोनो राज्यों मे सरकार के मुखिया अपनी सरकार बचाने के चक्कर में प्रदेश के सभी विभाग को पदाधिकारियों के हांथों में सौंपकर चैन की बंशी बजा रहे हैं और पदाधिकारी हर काम का Commision लेकर सरकार की जन-कल्याणकारी योजना का बंदरवाट करवा रहे हैं। दोनों राज्यों के Education एवं Health Department आवाम के लिए सबसे आवश्यक हैं लेकिन लूट की खुली छूट विभाग एवं जिला, अनुमंडल सहित प्रखंड के अधिकारी लालच की वजह से दे रखी है जिसकी वजह से सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है और जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता और तो और सरकार की जगहसाई भी होती है। बिहार में शिक्षा विभाग के तात्कालीन अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने P.M.H School को जन सुविधाओं से लैश करके सरकारी विद्यालयों की गौरवशाली अतित को लौटाना चाहते थे लेकिन कमीशनखोरी वाली गैंग ने टेबुल, बेंच, बोरिंग, शौचालय, बाउंड्री एवं निर्माण का कार्य करवाकर उसको हाईटेक बनाना चाहते थे लेकिन उनका विभाग से हटने के बाद सबकुछ सामने आने लगा है कि किस प्रकार सूचीबद्ध संवेदकों के अलावा मोटी कमाई के लिए स्थानीय लोगों को काम दिया जाने लगा। सूचीबद्ध कई संवेदकों के पास पैसा नहीं है और इस वजह से कई जगहों पर काम नहीं हो रहा है इसलिए DEO अपने स्तर से भी कुछ काम बाटने लगे तो झारखंड के अधिकारी जानते हुए भी उन 05 कंपनी को Computer Education के नाम करोड़ों को भुगतान बगैर कोई काम के दिए जा रहे हैं। खबर पर असर इसलिए नहीं हो रहा है की इससे विभाग एवं सरकार की बदनामी होगी लेकिन सच तो आज नहीं कल सबके सामने आने ही वाला है। झारखंड सरकार की महत्वकांक्षी योजना ICT Lab एवं Smart Classes के नाम पर सभी 24 जिलों में जमकर कंपनियों बिना Computer इंस्टॉल किये वर्षो से उसका भुगतान ले रही है। खबर छापने पर मिलकर बात करने की दुहाई दी जाती है। जिला स्तर के पदाधिकारी से जानकारी देने पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है यह राज्य स्तर का मामला है। एक IAS से कितनी उम्मीदे देश की जनता लगाये बैठी रहती है लेकिन जब वहीं सबकुछ जानकर अंजान बनने का नाटक करें तो इस महालूट के अभियान से प्रदेशों को कैसे बचाया जा सकता है, सवाल बनकर रह जाता है। GEM पोर्टल पर टेंडर होता है कहकर सरकार कोई L1 संवेदक को काम सौंपती है लेकिन उसकी सच्चाई क्या है यह सर्व-साधारण को भी ज्ञात है। दवा खरीदना हो या कोई उपकरण, मशीन खरीदनी हो या गाड़ियां, सड़क निर्माण हो या भवन निर्माण, स्कूल बनाना हो हॉस्पीटल सभी जगहों पर कमीशनखोरी का खेल बदस्तूर जारी है। बिहार में बालू (Red Gold) का भयंकर महालूट है तो झारखंड में कोयला (Black Gold) कालाबाजारी और नाम भी दिया जाता है, डिस्को। इन जगहों पर पोस्टिंग के लिए करोड़ों की बोली लगती है तभी वहां पदाधिकारी स्थायी रूप से 03 साल तक काम करते हैं चाहे बात SHO की हो या SP साहेब की। Public Tax से सरकार का खजाना भरता है और सरकार के मंत्री एवं अधिकारी ही उस खजाने को घुन की तरह चाटने लगेंगे तो देश में **भोजन का अधिकार अधिनियम** को लागू करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र और महात्मा गाँधी की रक्षा एवं सम्मान की बात करने वाले किस प्रकार **मनरेगा** को लूटते हैं किसी से छुपा है? भारत देश में जाति, धर्म, क्षेत्र और जनसंख्या देखकर नियम बनाये जाते रहेंगे उस देश में भ्रष्टाचार कोई अपराध नही बल्कि काम के बदले इनाम है की राजनीति चलती रहेगी और भ्रष्टाचारी अकूट संपत्ति जमा करेंगे और सेवानिवृत होने के बाद या उससे पहले MP, MLA बनकर उस अवैध संपत्ति की रक्षा करने में कामयाब भी हो जायेंगे। जिस अधिकारी ने 30 की बेहतरीन सेवा में जनता का विश्वास नहीं जीता वह नेता बनकर जनहित का काम कर पायेंगे?

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 14, अंकः- 157 माहः- जुलाई 2024 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Surjit Tiwary 9431222619
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565
Kamod Kumar Kanchan 8971844318

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922
Brajesh Sahay 7488696914

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203
Sagar Kumar 9155378519

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जून 2024

नहीं मिली राहत

मिश्रा जी,

संजय सिन्हा की खबर ''**केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत**'' में दिल्ली और आप पार्टी के विषय में संक्षिप्त ही सही लेकिन तथ्यों को हूबहू रखा है जो काबिले तारिफ है। Youtube पर sex से संबधित विषय पर भी दोनों आलेख काफी पठनीय है। जून 2024 अंक का सभी खबर एक पर एक है। अरबिन्द केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने की वजह से आप पार्टी के भीतर की बौखलाहट पर लिखा गया आलेख में संजय सिन्हां ने मुख्य बिन्दुओं को उठाया है। NEET और झारखंड में कम्प्यूटर घोटाला वाला खबर भी जानकारीप्रद है। ऐसी खबरो को प्राथमिकता मिलना चाहिए।

● **परितोष सिंह, घंटा घर, भागलपुर, बिहार**

घोटाला

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के जून 2024 अंक में झारखंड में हुए घोटाला पर सटीक एवं जानकारीप्रद खबर को सरकार एवं विभाग के बीच रखा है। रणवीर कुमार पाण्डेय की खबर ''**कोयला के बाद कम्प्यूटर घोटाला**'' में झारखंड सरकार एवं शिक्षा विभाग के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। किस प्रकार कंपनियों ने बिना काम का सरकार का खजाना पदाधिकारियों के मिलीभगत से किया है को उजागर करके आपने पत्रकारिता का कर्त्तव्य का निर्वहन किया है और निश्चित तौर पर सरकार एवं विभाग भी कुंभकर्णी नींद से जागेगी तो ठोस कार्रवाई भी अवश्य होगी। मजबूत एवं दमदार खबर है।

● **विवेक लकड़ा, करमटोली चौक, राँची**

भागवत कथा

संपादक महोदय,

जून 2024 अंक में अवधेश कुमार की खबर ''**मोहन भागवत के वक्तव्यों को कैसे देखें**'' में बहुत ही विचारणीय बिन्दुओं को पढ़ने को मिला। भाजपा और संघ के बीच चल रहे संघर्ष की अंदरूनी गाथा पर पर्दे में रहते हुए लिखा गया यह खबर सबकों सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिरकार संघ प्रमुख भागवत ने अपने वक्तव्य इस प्रकार क्यों रखें। जिस प्रकार देश में आईटी का इस्तेमाल असत्य परोसने के लिए किया जा रहा है वह निंदनीय है और चिंताजनक भी। देश का चुनाव सम्पन्न हो गया है और सबको अब चुनावी राजनीति से अलग होकर देशहित पर बात करना चाहिए। संघ ने पक्ष एवं विपक्ष दोनों को इसपर विचार करने की सलाह दी है।

● **आशीष पाठक, भोपाल रेलवे कॉलोनी, मप्र०**

वायनाड उपचुनाव

संपादक महोदय,

2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गाँधी दो क्षेत्रों से चुनाव में जीते थे इस वजह से वायनाड लोकसभा से अपनी बहन प्रियंका के लिए जगह छोड़ दिया। जून 2024 अंक में पत्रकार अमित कुमार की खबर ''**कयासों के ढ़ेर पर वायनाड लोकसभा का उपचुनाव**'' में आपने राजनीति एवं कांग्रेस का भविष्य पर बहुत हीं बेहतरीन खबर पाठकों के समक्ष रखा है। केवल सच टाइम्स पत्रिका की खबरें बहुत तथ्य के साथ एवं ज्वलंत मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाती है। यूपी और केरल के बीच की राजनीति को कांग्रेस से जोड़कर लिखना बेहद सटीक लगा। राहुल गाँधी और कांग्रेस की राजनीति पर दो पन्नों का यह आलेख काफी पठनीय है। मुझे यह खबर अच्छा लगा।

● **हरेन्द्र झा, बाबू बाजार, कोलकाता, प० बं०**

झटका

मिश्रा जी,

''INDIA को दिया MODI ने झटका'' केवल सच टाइम्स पत्रिका का जून अंक 2024 का संपदाकीय सच में बेजोड़ और संग्रहणीय है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव एवं उसके नतीजे सहित सरकार बनाने की कूटनीति पर सटीक समीक्षा आलेख में पढ़ने को मिला है। पूर्ण बेबाकी के साथ आपका संपादकीय में दोनों गठबंधनों के राजनीति एवं सत्ता के लिए लोक-लुभावन बयानों से अपने पक्ष में करने की मुहिम को भी अंकित किया गया है। NDA भारत देश को हिन्दू राष्ट्र तो INDIA गठबंधन मुस्लिम वोटर को गोलबंद करने में लगी रही और दोनों लोगों को अपने मुहिम में कामयाबी मिली। आपका आलेख आंख खोलने वाला है।

● **केशव राय, इटखोरी बाजार, चतरा, झा०**

पेपर लीक

ब्रजेश जी,

आपकी पत्रिका केवल सच टाइम्स का जून 2024 अंक में NEET पेपर लीक मामले को बहुत पुरजोर ढ़ंग से लिखा है। अमित कुमार की खबर ''**अधड़ में फंसा परिक्षार्थियों का भविष्य**'' में कब रूकेगी पेपर लीक की धाधली को पूर्ण बेबाकी से पाठक एवं सरकार के बीच रखने का सही प्रयास किया गया है जिसकी जमकर सराहना होनी चाहिए। NTA सहित विभाग की लापरवाही और पेपर लीक होने की पूरी दास्तां को हूबहू आलेख में लिखकर वस्तु स्थिति से रूबरू कराना वास्तव में वर्त्तमान समय की पंत्रकारिता में कठिन एवं जोखिमपूर्ण है। आलेख स्तरीय एवं काफी रोचक है। इस प्रकार की खबर से पत्रिका की साख बढ़ती है।

● **मो० अकिल, टावर चौक, बक्सर, बिहार**

अन्दर के पन्नों में

गैंगस्टर का एनकाउंटर पर बवाल.....39

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
व्यवसायी
पटना, बिहार
7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 || 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

117 खिलाड़ियों के साथ पेरिस ओलंपिक-2024 में शामिल हुआ भारत

● अमित कुमार

फैशन की राजधानी माने जाने वाले इस जगमगाते शहर में खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में दुनिया भर के 10500 से अधिक खिलाड़ी जब पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे तो 100 साल बाद पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेल हर मायने में अनूठे, अपारंपरिक और अप्रतिम होंगे। एक ओर एफिल टावर जैसी शहर की कई मशहूर जगहों के इर्द-गिर्द तस्वीरें खिंचवाने की होड़ मची दिखेगी तो मैदान पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में वर्चस्व की होड़ रहेगी। पेरिस ने ठीक 100 साल पहले अपने पिछले ओलंपिक की मेजबानी की थी। उस समय उसका वैश्विक खेल आयोजित करने का विचार काफी हद तक

शांति को बढ़ावा देने और दुनिया को एकजुट करने का था। सौ साल के बाद भी यह विचार कमोबेश कायम है लेकिन अब खेलों में उत्कृष्टता का महत्व अधिक हो गया है। खेलों को अब दुनिया में 'सॉफ्ट पावर' की तरह माना जाता है और जिस पर देश गर्व करना और दिखावा करना पसंद करते हैं। पेरिस में 1924 में हुए खेलों में 44 देशों के 3000 से कुछ अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की थी। लेकिन अब 'रोशनी का यह शहर' लगभग 10500 खिलाड़ियों की मेजबानी के लिए तैयार है। आम तौरपर ओलंपिक जैसे आयोजन के लिए नये खेल स्थलों का निर्माण होता है लेकिन पेरिस इस मामले में अनूठा है क्योंकि यह शहर खुद ही आयोजन स्थल बन गया है। इन खेलों का 95 प्रतिशत आयोजन पुराने

या अस्थायी स्थल पर होगा। इन खेलों के लिए नए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर पैसा खर्च करने के बजाय, बजट का उपयोग मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और शहर की प्रसिद्ध जगहों के आसपास अस्थायी स्थल का निर्माण करने के लिए किया गया जो प्रभावशाली पृष्ठभूमि के रूप में काम करेंगे। बीचबॉल का आयोजन एफिल टॉवर के ठीक बगल में होगा। शानदार इंजीनियरिंग का यह चमत्कार दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाता रहता है। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया जाएगा। हॉल तक पेरिस के शहरी नियोजन के उप महापौर इमैनुएल ग्रेगोइरे ने कहा कि ''हमने ओलंपिक को शहर के हरित क्षेत्र में बढ़ावा लाने के शानदार अवसर के तौर पर देखा है। हमने सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन, नदी को काफी हद तक बदल दिया है। इन खेलों के बिना इस तरह के सकारात्मक बदलाव के लिए एक या दो दशक और लग सकते थे।'' इन व्यवस्थाओं की कीमत हालांकि स्थानीय लोगों को चुकानी पड़ रही है। लोगों के लिए बिना किसी वैध कारण के शहर में प्रवेश करना बेहद मुश्किल हो गया है। स्थानीय छात्र सैलोम ने पीटीआई को बताया कि 'न्यू पेरिस में आप बिना किसी मजबूत कारण के प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक अनुरोध करना होगा और यदि मंजूरी मिल जाती है तो आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसके साथ आप शहर में प्रवेश करेंगे।' सैलोम को अपने अभिभावकों के घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि 'बहुत से लोगों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है, खासकर उन्हें जो आयोजन स्थल के पास रह रहे हैं। ओलंपिक स्थलों के पास की इमारतों का उपयोग अब आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। ज्यादातर सुरक्षा कर्मचारी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।' इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ''मई में हमारी परीक्षाएं थीं और हमें अप्रैल में जाने के लिए कहा गया था। हम सितंबर में ही वापस आ सकते हैं। हमें मुआवजे के तौर पर 100 यूरो और ओलंपिक के लिए दो टिकट मिले हैं।'' एक स्थानीय वालंटियर ने कहा कि 'उद्घाटन समारोह सीन नदी पर होगा लेकिन उसके लिए जिन लोगों को मुफ्त प्रवेश नहीं मिल रहा है उनके लिए टिकट की न्यूनतम कीमत 900 यूरो है। पेरिस में औसत आय 1400 यूरो प्रति माह है। ऐसे में टिकट की कीमत बहुत अधिक है। आयोजक निमंत्रण के आधार पर दो लाख से अधिक लोगों को मुफ्त प्रवेश की पेशकश कर रहे हैं। उन्हें नदी के ऊपरी तट तक पहुंच प्रदान की जाएगी। यह निमंत्रण चुनिंदा निवासियों और स्थानीय खेल प्रशासकों को भेजे जाएंगे। इन खेलों में सकारात्मक बात यह है कि खेलों को 'सर्कुलर इकोनॉमी' मॉडल पर किया जा रहा है। जिसका अर्थ है कि मौजूदा सामग्री को जितना संभव हो उतना साझा करना, पट्टे पर देना, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण करना है। खेल आयोजकों के अनुसार, खेल योजना में 'सस्टैनबिलिटी (स्थिरता) महत्वपूर्ण थी और इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किये गये है। पेरिस ओलंपिक में कम संसाधनों का बेहतर उपयोग किया गया है। इन खेलों के दौरान उपयोग किए जाने वाले खेल उपकरण मोटे तौर पर 20 लाख की संख्या में होने का अनुमान है, जिनमें से 15 लाख खेल महासंघों को उधार या किराये पर दिये जायेंगे। खेलों के दौरान इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर और प्रिंटर भी किराए पर दिए जाएंगे। बेहतर उपयोग के लिए कम संसाधनों का उपयोग करने की नीति का पालन करते हुए, फर्नीचर से जुड़ी वस्तुओं की संख्या भी शुरुआत में अनुमानित आठ लाख से घटाकर छह लाख कर दी गई है। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा और पिछले ओलंपिक की तुलना में संख्या 40 प्रतिशत तक कम कर दी गई है। जनरेटर भी जैव ईंधन, हाइड्रोजन या बैटरी द्वारा संचालित होंगे। इन खेलों के लिए बहुत कम नये स्थलों का निर्माण किया गया है। आयोजकों ने कई खेलों के लिए शहर की प्रतिष्ठित और वास्तुशिल्प वाली जगहों की पृष्ठभूमि का उपयोग करने की एक

बहुत ही प्रभावी रणनीति अपनायी है। आयोजक खेलों के 329 आयोजनों का प्रबंधन या तो पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे या अस्थायी स्थानों पर कर रहे हैं, जो कुल संख्या का 95 प्रतिशत है। 35 प्रतियोगिता स्थलों में से, केवल दो नए मैदान बनाए गए हैं और उनमें से एक 'एक्वेटिक्स सेंटर' को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया है। आयोजन स्थल की सीटें पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बनाई गई हैं और इसे रणनीतिक रूप से ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहां शहर में खेल के बुनियादी ढांचे की कमी है। दूसरा नया स्थल 'पोर्टे डे ला चौपल एरेना' है। इसके साथ ही इस ओलंपिक में खास बात है कि पहली बार, 10,500 खिलाड़ियों में से आधी महिलाएं होंगी, जो लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तोक्यो में पिछले सत्र में महिला खिलाड़ियों की संख्या कुल प्रतिभागियों का 47.8 प्रतिशत थी।

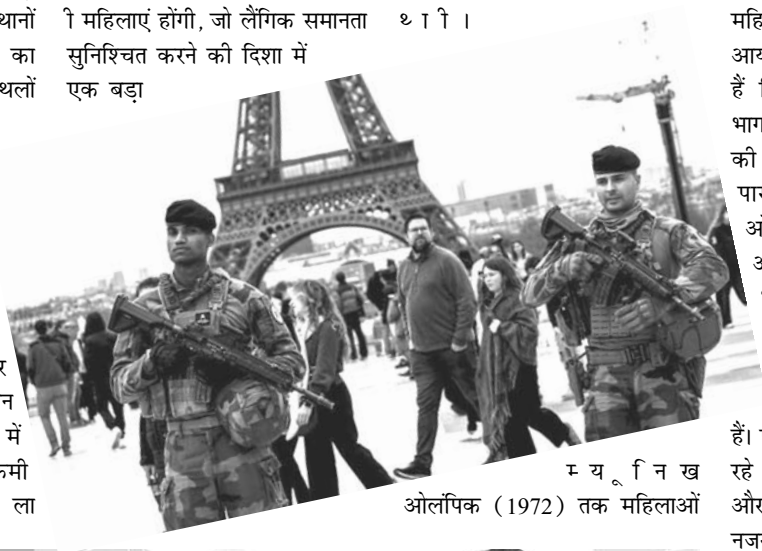

म्यूनिख ओलंपिक (1972) तक महिलाओं की भागीदारी 20 प्रतिशत से भी कम थी। पेरिस खेलों का पारंपरिक समापन समारोह पुरुषों की बजाय महिलाओं की मैराथन होगी और इस आयोजन में 32 में से 28 ऐसे खेल हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेंगे। और तो और ग्यारह बरस की स्केटबोर्ड खिलाड़ी से लेकर 60 पार के घुड़सवार तक, पेरिस ओलंपिक में हर उम्र के खिलाड़ी अपनी चमक बिखेरते नजर आयेंगे। भारतीय दल में भी चौदह साल की तैराक धिनिध देसिंघु भी है जो 44 बरस के टेनिस दिग्गज रोजन बोपन्ना से प्रेरणा ले सकती हैं। पीटीआई ने 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में सबसे छोटे और सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों पर नजर डाली है :-

☞ **झेंग हाओहाओ (चीन, स्केटबोर्डिंग):-** ग्यारह वर्ष और 11 महीने की स्केटबोर्डर झेंग पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वह अब तक सबसे युवा ओलंपियन रहे यूनानी जिम्नास्ट दिमित्रोस लाउंडरास से एक साल बड़ी है। दिमित्रोस ने 1896 में दस वर्ष 218 दिन की उम्र में पहला ओलंपिक खेला था। 11 अगस्त को 12 वर्ष की हो रही झेंग ने बुडापेस्ट और शंघाई में क्वालीफिकेशन सीरिज के बाद पेरिस का टिकट कटाया। मजे के लिये स्केटबोर्डिंग खेलना शुरू करने वाली झेंग ने कहा कि

झेंग हाओहाओ

जिल इरविंग

धिनिध देसिंघु

रोहन बोपन्ना

'किसी ने मुझे बोला कि स्केटबोर्डिंग में बहुत मजा आता है और वाकई यह सच था। मैने तोक्यो ओलंपिक क्वालीफायर में पहली बार एक लड़की को स्केटबोर्डिंग करते देखा तो मुझे वह बहुत कूल लगी।'

☞ **जिल इरविंग (कनाडा, घुड़सवारी) :-** कनाडा की घुड़सवारी टीम की सदस्य जिल इरविंग 61 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में पदार्पण करेंगी। आस्ट्रेलिया की मेरी हान्ना 1996 अटलांटा ओलंपिक से छह ओलंपिक खेल चुकी हैं और 69 वर्ष की उम्र में घुड़सवारी टीम (ड्रेसेज) में रिजर्व खिलाड़ी हैं और शायद प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका नहीं मिले। आस्ट्रेलियाई टीम में किसी के चोटिल या बीमार होने पर ही उन्हें बुलाया जायेगा। ओलंपिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्वीडन के निशानेबाज आस्कर स्वान थे जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेला था।

☞ **धिनिधि देसिंघु (तैराक, सबसे युवा भारतीय) :-** चौदह वर्ष और दो महीने की धिनिधि देसिंघु महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में उतरेंगी और भारतीय दल की सबसे युवा सदस्य हैं। बेंगलुरू में नौवी कक्षा की छात्रा देसिंघु ने यूनिवर्सिलिटी कोटा के जरिये ओलंपिक के लिये क्वालीफाई किया। इसके तहत अगर किसी देश के खिलाड़ी सीधे क्वालीफिकेशन की पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो दो शीर्ष खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। देसिंघु भारतीय दल में दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी हैं। तैराक आरती साहा 11 वर्ष की थी जब उन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक खेला था।

☞ **रोहन बोपन्ना (टेनिस, सबसे उम्रदराज भारतीय) :-** 44 वर्ष और चार महीने के बोपन्ना पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं। वह तीसरा ओलंपिक खेल रहे हैं और पुरूष युगल में श्रीराम बालाजी के साथ उतरेंगे। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में महेश भूपति के साथ पदार्पण किया था। रियो ओलंपिक में वह लिएंडर पेस के साथ दूसरे दौर में हार गए। मिश्रित युगल में वह और सानिया मिर्जा कांस्य पदक से एक जीत दूर पहुंचे थे। जनवरी में एटीपी युगल रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे बोपन्ना ने 43 वर्ष की उम्र में आस्ट्रेलियाई ओपन पुरूष युगल खिताब जीता। वह सिडनी जैकब के बाद ओलंपिक के लिये क्वालीफाई करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी हैं। जैब ने 44 वर्ष 267 दिन की उम्र में पेरिस ओलंपिक 1924 में पुरूष युगल खेला था। भारत के सबसे उम्रदराज ओलंपियन स्कीट निशानेबाज भीम सिंह बहादुर हैं जिन्होंने 1976 मांट्रियल ओलंपिक में भाग लिया तब वह 66 वर्ष के थे। भारतीय दल में 42 वर्ष के अचंत शरत कमल और 40 वर्ष के तीरंदाज तरूणदीप राय भी हैं।

बहरहाल, पेरिस ओलंपिक के लिये यहां पहुंचे करीब 45000 वालिंटियर का यहां आना सार्थक हो गया जब उन्हें हवाई अड्डे पर टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज से मिलने का मौका मिला। पेरिस में सौ साल बाद ओलंपिक हो रहे हैं और वालिंटियर्स के लिये यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव है। पेरिस हवाई अड्डे पर एक उत्साही वालिंटियर ने कहा कि 'मैं 60 साल का हो चुका हूं और मेरे जीवन में तो पेरिस में फिर ओलंपिक नहीं होने वाला। इसका हिस्सा बनना मेरे लिये जीवन भर नहीं भूलने वाला अनुभव है।' उन्होंने कहा कि, 'बीस मिनट पहले अल्काराज यहां पहुंचा और मैने उसे एक्रिडिटेशन (पहचान पत्र) दिलाने में मदद की। यह अनुभव यादगार हो गया है।' किन्तु पेरिस में रहने वाले सभी लोग ओलंपिक के आयोजन से खुश नहीं है क्योंकि इसका उनके दैनंदिनी जीवन पर असर पड़ रहा है। स्थानीय यातायात 2.15 यूरो से बढकर चार यूरो तक पहुंच गया है और आठ सितंबर को पैरालम्पिक के खत्म होने तक यही किराया रहेगा। ओलंपिक आयोजन स्थलों के आसपास आवागमन पर भी पाबंदियां हैं। शहर के सबसे व्यस्त ट्रेन स्टेशन पर खड़ी विक्टोरी डेलारू ने कहा कि 'पेरिसवासियों के लिये ओलंपिक की मेजबानी गर्व का विषय है लेकिन इससे लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिये। स्थानीय यातायात की दरें दुगुनी हो गई है जो अच्छी बात नहीं है।' इसके साथ ही ओलंपिक के दौरान होटलों की भारी मांग दिखाई गई जिससे पेरिस के कई

खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेरिस ओलंपिक को लेकर बैठक की

लोगों ने कमाई के लिये अपने घरों को किराये पर लगा दिया लेकिन होटलों की उतनी मांग है नहीं। पेरिस में यह पर्यटन का मौसम है लेकिन मांग फिर भी कम है। एक होटल के मैनेजर समीर ने कहा कि 'इस समय हमारे होटल में एक रात का किराया 120 यूरो रहता है लेकिन हम आधे दाम पर लगा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि 'ओलंपिक की मेजबानी हमारे लिये अच्छी नहीं रही। काफी पाबंदियां हैं और कई जगहों पर जाने के लिये क्यूआर कोड चाहिये।' बता दें कि ओलंपिक के लिये स्थानीय प्रशासन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीन नदी की सफाई था जहां उद्घाटन समारोह, ट्रायथलन और मैराथन तैराकी होनी है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पानी पर उद्घाटन समारोह हो रहा है जिसमें सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीन नदी में तैराकी पर सौ साल पहले प्रतिबंध लग गया था लेकिन इसकी सफाई पर डेढ अरब यूरो खर्च किये गए। पेरिस के मेयर एन्ने हिडाल्गो ने

एन्ने हिडाल्गो

बारंबार देरी के बाद आखिरकार डुबकी लगाकर इसे तैराकी के लिये सुरक्षित करार दिया।

गौरतलब है कि अन्य देशों के साथ ही पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। सहयोगी स्टाफ के 72 सदस्यों को सरकार के खर्चे पर मंजूरी मिली है। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया था उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। विश्व रैंकिंग के जरिए कोटा हासिल करने वाली आभा खटुआ का नाम हटाने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले विश्व एथलेटिक्स की ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया था। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चोट लगने, डोपिंग उल्लंघन या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण उनका नाम हटाया गया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारी गोला फेंक एथलीट आभा खटुआ ने हाल में परिवार में हुए हादसे के बावजूद ओलंपिक में भाग लेने का फैसला किया था लेकिन उनका नाम पेरिस जाने वाले भारतीय दल से गायब है और अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है कि उनका नाम सूची से क्यों हटा दिया गया। आभा 11 जुलाई को अपने अन्य साथियों के साथ भारत के ओलंपिक जाने वाले एथलेटिक्स दल के 'बेस' तुर्किये के स्पाला के लिए गई थीं। लेकिन अगले ही दिन विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी ट्रैक और फील्ड ओलंपिक प्रतिभागियों की सूची में उनका नाम नहीं था। विश्व रैंकिंग के जरिये पेरिस के लिए क्वालीफाई करने वाली 29 वर्षीय आभा का नाम फिर खेल मंत्रालय द्वारा मंजूर 117 सदस्यीय भारतीय दल से भी नदारद था। ट्रैक और फील्ड टीम में अब 29 सदस्य हैं जबकि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) द्वारा 30 सदस्यों की

इमैनुएल ग्रेगोइर

घोषणा की गई थी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के पास खुर्शी गांव में एक किसान के घर जन्मी आभा ने पांच साल पहले गोला फेंक में आने से पहले कई तरह के ट्रैक और फील्ड खेलों में हाथ आजमाया। उन्होंने 11 जुलाई को भारत से रवाना होने से पहले पीटीआई से बात करते हुए खुलासा किया कि हाल में अपनी भाभी (भाई की पत्नी) के निधन के बावजूद वह ओलंपिक में पदार्पण करेंगी। आभा ने स्वीकार किया था कि वह सदमे में थीं क्योंकि वह अपनी भाभी के काफी करीब थीं लेकिन उन्होंने अपने माता-पिता के बलिदान को देखते हुए ओलंपिक में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, 'मैंने कुछ दिन पहले अपनी भाभी को खो दिया जिससे मैं मानसिक रूप से बहुत निराश हूं। पेरिस खेलों के लिए क्वालीफाई करने के बाद मैं उत्साहित थी क्योंकि ओलंपियन बनना हर एथलीट का सपना होता है।' उन्होंने कहा था कि 'इस परिवार में इस हादसे के कारण मुझे झटका लगा। मैं अपने पहले ओलंपिक में भाग ले रही हूं। मेरे माता-पिता ने मुझे ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करते

आभा खटुआ

हुए देखने के लिए बहुत बलिदान किये हैं।' आभा खटुआ का नाम शामिल नहीं होने के बावजूद खिलाड़ियों की सूची में सर्वाधिक 29 (11 महिला और 18 पुरुष) खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं। उनके बाद निशानेबाजी (21) और हॉकी (19) का नंबर आता है। टेबल टेनिस में भारत के आठ जबकि बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित सात खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती (6), तीरंदाजी (6) और मुक्केबाजी (6) में छह-छह खिलाड़ी ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके बाद गोल्फ (4), टेनिस (3), तैराकी (2), सेलिंग (2) का नंबर आता है। घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन में एक-एक खिलाड़ी भाग लेंगे। निशानेबाजी दल में 11 महिला और 10 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। टेबल टेनिस में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में चार-चार खिलाड़ी शामिल हैं। तोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू दल में शामिल एकमात्र भारोत्तोलक हैं। वह महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। तोक्यो ओलंपिक में भारत के 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिन्होंने सात पदक जीते थे। इनमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में जीता गया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। चोपड़ा पेरिस में अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेंगे। दल में शामिल में 21 अधिकारियों में 11 खेल गांव में रुकेंगे जबकि बाकी अधिकारी खेल गांव के बाहर होटल में ठहरेंगे। इनका खर्च सरकार वहन करेगी। निशानेबाजी में सहयोगी स्टाफ के सर्वाधिक 18 सदस्य शामिल हैं जिनमें से एक हाई परफॉर्मेंस निदेशक और छह कोच खेल गांव में ठहरेंगे। बाकी 11 सदस्य होटल में रुकेंगे जिनमें चार कोच, चार फिजियो, दो मनोवैज्ञानिक और एक अनुकूलन विशेषज्ञ शामिल हैं। एथलेटिक्स में सहयोगी स्टाफ के 17 सदस्य शामिल हैं। उसके बाद कुश्ती (12), मुक्केबाजी (11), हॉकी (10), टेबल टेनिस (9), बैडमिंटन (9), गोल्फ (7), घुड़सवारी (5), तीरंदाजी (4), नौकायन (4), भारोत्तोलन (4) टेनिस (3), तैराकी (2) और जूडो (1) का नंबर आता है। मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि पेरिस में भारतीय दूतावास में एयर अताशे पद पर कार्यरत एयर कमोडोर प्रशांत आर्य ओलंपिक अताशे होंगे, जिनके पास मान्यता पत्र होगा तथा वह दूतावास की सहायता और

अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया

हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले किसी भी मुद्दे का समाधान करने के लिए खेल गांव और प्रतियोगिता स्थलों का दौरा करेंगे। वही ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले अन्य खिलाड़ियों को उम्मीद के अनुरूप मंजूरी मिल गई। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को दल प्रमुख बनाया गया है। नारंग भारतीय ओलंपिक संघ में उपाध्यक्ष भी हैं। खेल मंत्रालय की ओर से आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 'ओलंपिक खेल 2024 की आयोजन समिति के मानदंडों के अनुसार सहयोगी स्टाफ के 67 सदस्य ही खेल गांव में रुक सकते हैं जिनमें आईओए के 11 अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों में पांच सदस्य चिकित्सा दल के हैं।' पत्र में कहा गया है कि 'खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की लागत पर 72 अतिरिक्त कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों को मंजूरी दी गई है और उनके ठहरने की व्यवस्था होटल-खेल गांव के बाहर के स्थानों में की गई है।'

बताते चले कि अपने देश के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले अग्रणी भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 'ओलंपिक ऑर्डर' से सम्मानित करने का फैसला किया है।' 'ओलंपिक ऑर्डर' आईओसी का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए नामांकन ओलंपिक ऑर्डर समिति द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 'ओलंपिक ऑर्डर' से सम्मानित होने पर बिंद्रा को बधाई दी।

ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। आईओसी अध्यक्ष ने 20 जुलाई को बिंद्रा को संबोधित एक पत्र में लिखा कि 'मुझे आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने ओलंपिक आंदोलन में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि 'ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई।' उन्होंने कहा कि 'उनकी उपलब्धि हमें गौरवान्वित करती है और वह वास्तव में इसके योग्य है। उन्होंने निशानेबाजों और ओलंपिक में भाग लेने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है।' अब 41 साल के हो चुके बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। वह ओलिंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। वह 2010 से 2020 तक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की एथलीट समिति के सदस्य थे जिसमें वह 2014 से इसके अध्यक्ष रहे। वह 2018 से आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए 328 मैच खेलने वाले श्रीजेश का यह चौथा ओलंपिक होगा। कई राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और विश्व कप में खेल चुके 36 साल के श्रीजेश ने 2021 में आयोजित हुए तोक्यो ओलंपिक में शानदार गोलकीपिंग से भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने तब इस खेल में 41 साल के पदक के सूखे को खत्म किया था। हॉकी इंडिया ने श्रीजेश को उनके शानदार करियर के लिए

भोला नाथ सिंह

गगन नारंग

डॉ. दिलीप तिर्की

हरमनप्रीत सिंह

बधाई दी। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय टीम के लिए 'विन इट फॉर श्रीजेश (श्रीजेश के लिए जीतना है)' का अभियान शुरू किया है जो खिलाड़ियों को फिर से पदक जीतने लिए प्रेरित करेगा। श्रीजेश ने भारतीय टीम के लिए 2010 में पदार्पण किया था। वह 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। वह 2018 में एशियाई चौंपियंस ट्रॉफी की संयुक्त विजेता टीम, भुवनेश्वर में 2019 एफआईएच पुरुष सीरीज फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता टीम और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2021-22 में भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीजेश को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर' 2021 का पुरस्कार जीतने वाले भारत के केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2021 और 2022 में में लगातार दो बार एफआईएच साल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। उन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया जिससे भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 का टिकट पक्का करने में सफल रही। श्रीजेश ने हॉकी इंडिया से जारी विज्ञप्ति में कहा कि 'मैं पेरिस में अपने आखिरी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे अपने करियर पर बहुत गर्व है और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मेरी अब तक की यात्रा असाधारण रही है और मैं अपने परिवार, टीम के साथियों, सभी कोच, प्रशंसकों और हॉकी इंडिया के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी हूं। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद।' श्रीजेश ने कहा कि उन्होंने टीम के साथियों को ओलंपिक के बाद संन्यास लेने के फैसले से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि 'मेरे टीम के साथी मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहे हैं। हम सभी यहां पेरिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से अपने पदक का रंग बदलना चाहते है।' हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने श्रीजेश को उनके शानदार करियर के लिए बधाई देते हुए कहा कि 'श्रीजेश मुश्किल से 18 या 19 साल के थे जब मैंने उन्हें पहली बार भारतीय शिविर में देखा था और अगर मुझे सही याद है, तो जब मैं कप्तानी कर रहा था तब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में पदार्पण किया था।' इस पूर्व कप्तान ने कहा कि 'वह एक बहुत ही विशेष खिलाड़ी हैं और भारतीय हॉकी में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए मेरा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया है।' तिर्की को उम्मीद है कि श्रीजेश के इस फैसले से टीम के खिलाड़ी अपने चहेते गोलकीपर को शानदार विदाई देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि 'पेरिस में यह दौरा निश्चित रूप से टीम के लिए विशेष होगा और मेरा मानना है कि श्रीजेश का निर्णय टीम को और फिर से पदक जीतने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा। पोडियम पर फिर से खड़े होने और इसे न केवल श्रीजेश के लिए बल्कि पूरी हॉकी बिरादरी के लिए विशेष बनाने के लिए मैं उन्हें और टीम को शुभकामनाएं देता हूं।' भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम ने पेरिस का अपना अभियान श्रीजेश के लिए समर्पित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 'पेरिस 2024 वास्तव में एक विशेष टूर्नामेंट होगा। हमने अपना अभियान दिग्गज पीआर श्रीजेश को समर्पित करने का फैसला किया है। वह हम सभी के लिए प्रेरणा हैं।' हरमनप्रीत ने अपने खेल के शुरूआती दिनों को याद करते हुए कहा कि 'मुझे अब भी 2016 जूनियर विश्व कप में उनकी सलाह याद है जब हमने खिताब जीता। उन्होंने हम में से कई खिलाड़ियों के करियर को संवारा है। हम इसे 'विन इट फॉर श्रीजेश' करना चाहते हैं।' हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने श्रीजेश को दिग्गज खिलाड़ी करार देते हुए कहा कि हॉकी इंडिया उनके फैसले की सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि 'श्रीजेश दिग्गज खिलाड़ी है।

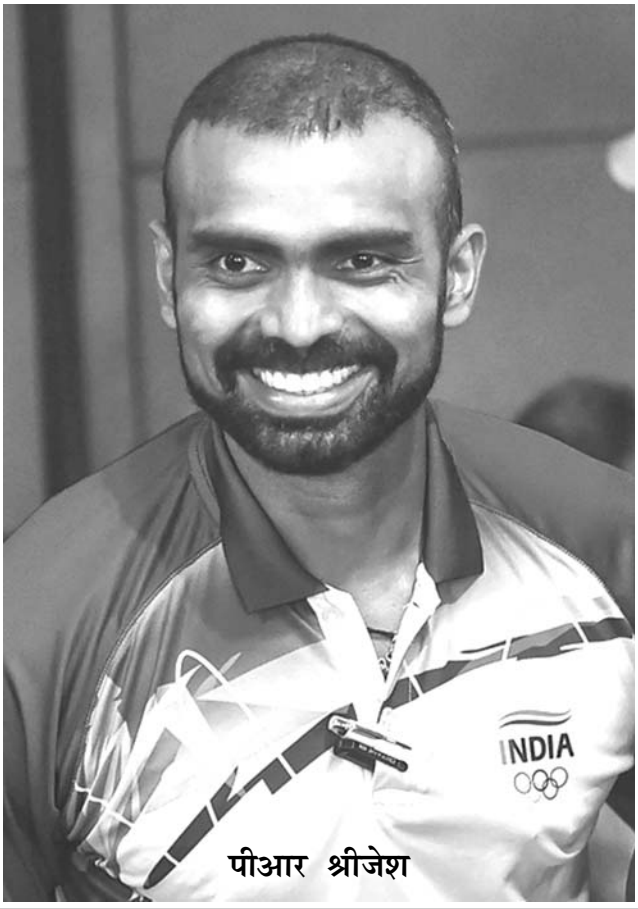

पीआर श्रीजेश

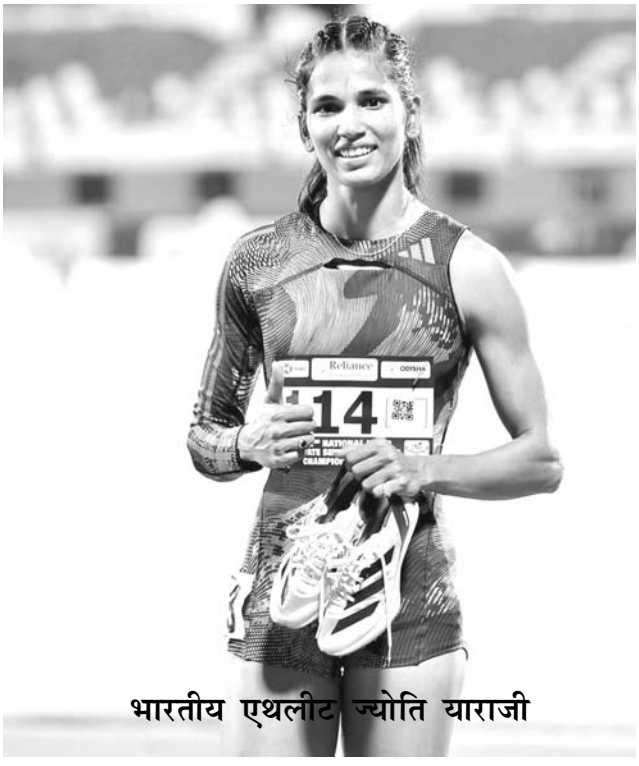

भारतीय एथलीट ज्योति याराजी

बीसीसीआई सचिव जय शाह

वह पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं और मैं उन्हें कई उपलब्धियों से भरे शानदार करियर के लिए बधाई देता हूं, जिसने देश को सम्मान और गौरव दिलाया है।' उन्होंने कहा कि 'हॉकी इंडिया पेरिस ओलंपिक खेलों के बाद संन्यास लेने के उनके फैसले का सम्मान करता है, जिससे यह न केवल टीम के लिए बल्कि भारतीय हॉकी प्रशंसकों के लिए भी एक विशेष टूर्नामेंट बन गया है। मैं उन्हें और टीम को उनके अभियान के लिए शुभकामनाएं देता हूं।'

अब बात भारतीय एथलीट ज्योति याराजी की करे तो 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन जाएगी, जिसमें उनकी कोशिश अपनी मां के अभी तक के सारे संघर्षों को खत्म करने की होगी। विश्व रैंकिंग कोटे से ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली याराजी अपनी मां की सकारात्मक सोच से प्रेरित होकर पेरिस में शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगी। उनकी माँ विशाखापत्तनम में एक स्थानीय अस्पताल में सफाईकर्मी और घरेलू सहायिका की 'डबल शिफ्ट' में काम करती थीं। 'रिलायंस फाउंडेशन' द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बातचीत में याराजी ने कहा कि 'पहले मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, अपने परिवार और पृष्ठभूमि को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। लेकिन मैंने काफी कुछ सीखा है।' उन्होंने कहा कि 'कभी कभार मेरी हालत बहुत खराब होती। मेरी मां हमेशा मुझे कहती कि आगे बढ़ते रहो क्योंकि हम वर्तमान, अतीत और भविष्य को नहीं रोक सकते।' याराजी ने कहा कि 'मेरी मां ने मुझे कहा, तुम अपने लिए काम करो, कोई भी नतीजा रहे, हम इसे स्वीकार करेंगे। मेरी माँ प्रतियोगिता से पहले मुझे कभी नहीं कहतीं कि पदक जीतो या फिर स्वर्ण पदक जीतो। वह मुझसे कहतीं कि जाओ स्वस्थ रहो और जो भी मैं करूं उसमें संतुष्ट रहूं। इसलिए मैं हमेशा सकारात्मक सोच से आगे बढ़ती हूं।' उन्होंने यह भी कहा कि सकारात्मक सोच के लोगों के साथ रहने से भी उन्हें मदद मिली क्योंकि उन्होंने अतीत और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय मेरे वर्तमान को सुधारने में मदद की। याराजी ने अपने कोच जेम्स हिलीयर (रिलायंस फाउंडेशन के एथलेटिक्स निदेशक) का जिक्र करते हुए कहा कि 'पहले मेरे पास अच्छी टीम नहीं थी। अब मेरे साथ बहुत सारे सकारात्मक लोग हैं। इससे मुझे काफी मदद मिल रही है। मैं हमेशा सकारात्मक रहती हूं। मैं सकारात्मक सोच से नकारात्मकता को दूर करती हूं।' याराजी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12. 78 सेकेंड का है और वह मानती हैं कि ओलंपिक पदार्पण में उन पर काफी दबाव होगा लेकिन वह ध्यान लगाकर शांत बने रहने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि 'मुझे ओलंपिक में खेलने का अनुभव नहीं है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये अच्छे रहेंगे। मुझे एशियाई चैम्पियनशिप, एशियाई खेल और विश्व चैम्पियनशिप का अनुभव है। मुझे उम्मीद है कि इनसे मिले अनुभव का ओलंपिक में फायदा उठाऊंगी।'

बहरहाल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रूपए देने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा कि ''मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अविश्वसनीय एथलीटों का समर्थन करेगा। हम इस अभियान के लिए आईओए को 8.5 करोड़ रुपये प्रदान कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि 'हम पूरे दल को शुभकामनाएं देते हैं। भारत को गौरवान्वित करें। जय हिंद।'

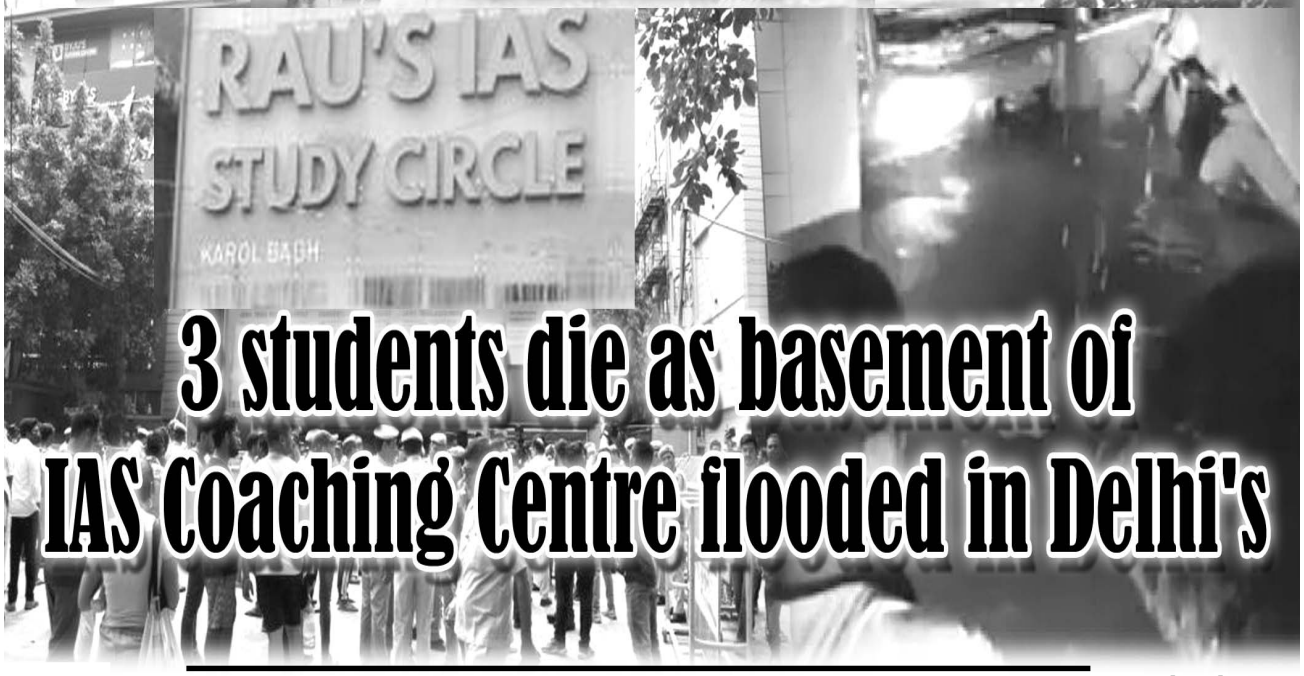

3 students die as basement of IAS Coaching Centre flooded in Delhi's

Three students died after the basement of a building housing a popular coaching centre was flooded following heavy rain in central Delhi's Old Rajinder Nagar area. The bodies of the three civil services aspirants, two female and a male, were retrieved from the basement of Rau's IAS Study Circle during the rescue operation by the National Disaster Response Force (NDRF), local police, and fire department, officials said. According to the Delhi Fire Department (DFS), a call about waterlogging was received from the coaching centre at around 7 pm on Saturday about students being trapped inside the coaching's basement, which was flooded follow-

ing a heavy downpour.

"The caller told us that there was a possibility that some people were trapped. We are investigating how the entire basement was flooded. It appeared that the basement got flooded very fast due to which some people were trapped inside," DCP (Central Delhi) M Harshavardhan said, as per a report by news agency PTI. An FIR was registered in the incident.

Delhi Water Minister Atishi assured that "whoever is responsible for the incident will not be spared". "There is news of an accident due to heavy rain in Delhi in the evening. There is news of water filling in the basement of a coaching institute in Rajendra Nagar. Delhi Fire Department and NDRF are on the spot. Delhi Mayor and local MLA are also there. I am taking updates of the incident every minute. A magistrate has been ordered to investigate how this incident happened. Whoever is responsible for this incident will not be spared…" she wrote in an X post. BJP MP Bansuri Swaraj hit out at Chief Minister Arvind Kejriwal and Rajender Nagar MLA Durgesh Pathak saying "they did not listen to requests of the local people to get the drainage systems cleaned". "There are still 2.5 feet of waterlogged on the street… Arvind Kejriwal and Durgesh Pathak are responsible for the deaths…" she said.

Delhi Mayor orders action against coaching centres operating from basements

Delhi Mayor Shelly Oberoi on Sunday ordered strict action against all coaching centres operating from basements following the death of three UPSC aspirants due to drowning in a water-flooded basement in Old Rajinder Nagar. She directed the Commissioner of the Municipal Corporation of Delhi to conduct a prompt investigation into this tragic incident and take strict action if any MCD officer is found guilty. In a letter to the MCD Commissioner, Oberoi said, "Yesterday some students were trapped in a private coaching institute being run in Rajendra Nagar due to flooding, and out of them, three students lost their lives. This is very shocking; this incident needs thorough investigation and strongest possible action." "It is also our responsibility to ensure that such an incident does not recur in any part of Delhi," she added. She further directed the MCD commissioner, coaching centres across Delhi that are under the jurisdiction of MCD and running commercial activities in basements that are in violation of building bye-laws and are not as per norms, strict action should be taken against them immediately." "An immediate inquiry should be conducted to identify if any officers of MCD are responsible for this tragedy. If any official is found guilty, the strongest possible action will be taken against them, under intimation to the undersigned," Oberoi said.

केजरीवाल की जिंदगी से खेल रही है भाजपा

● **संजय सिन्हा**

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई। न्यायाधीश ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को वीडियो

कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले ईडी द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी लेकिन वह तिहाड़ जेल में ही बंद रहे क्योंकि उन्होंने मामले में जमानती मुचलका नहीं भरा। केजरीवाल सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

गौरतलब है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के उन दावों को 'झूठा' और 'भ्रामक' बताकर खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि उसके पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सेहत बिगड़ रही है। वहीं आप नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल का वजन जेल में केवल दो किलोग्राम कम हुआ है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का एक चिकित्सा बोर्ड उनकी नियमित निगरानी कर

रहा है। आप की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने फिर से आरोप लगाया कि भाजपा केजरीवाल को स्थाई रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उनका रक्त शर्करा पांच बार 50 मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर तक गिर गया है। आतिशी ने दावा किया कि वह (केजरीवाल) कोमा में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि जब भी केजरीवाल के मामले में अदालत में सुनवाई करीब होती है, तो 'आप' नेता चिकित्सा मुद्दों के बारे में 'बयानबाजी' का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें जमानत मिल सके। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जब भी केजरीवाल के मामले में अदालत में सुनवाई नजदीक आती है, तो आप नेता बयानबाजी करने लगते हैं कि वह वजन घटने और रक्त शर्करा के स्तर में गिरावट जैसी चिकित्सीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, केजरीवाल हर दिन जेल में घर का बना खाना खाते हैं। अगर उनका वजन कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनके भोजन में पोषक तत्वों की कमी है और ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि उनको जमानत मिल सके। आतिशी ने दावा किया था कि केजरीवाल, जो मधुमेह के रोगी हैं, को 8.5 किलोग्राम वजन घटने और खतरनाक रूप से कम रक्त शर्करा स्तर के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। आतिशी ने कहा कि चिकित्सक आपको बताएंगे कि जब मधुमेह के रोगी का शुगर स्तर अचानक गिर जाता है तो यह घातक होता है और 20-30 मिनट के भीतर वह व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसे 'ब्रेन स्ट्रोक' और रक्तस्राव का सामना करना पड़ सकता है और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वही आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केजरीवाल की जान को खतरे में डाल दिया है।

उन्होंने भाजपा से दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ करने और इस पर राजनीति करना बंद करने के लिए कहा। दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट में तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल के बारे में जानकारी साझा की और कहा कि आप मंत्रियों और नेताओं द्वारा गढ़ी गई कहानी जनता को भ्रमित और गुमराह करती है। तिहाड़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब केजरीवाल पहली बार एक अप्रैल को जेल आए थे तो उनका वजन 65 किलोग्राम था और आठ से 29 अप्रैल के बीच उनका वजन 66 किलो था। रिपोर्ट के मुताबिक, 21 दिन की जमानत के बाद जब वह दो जून को जेल लौटे तो उनका वजन 63.5 किलोग्राम था। रिपोर्ट में कहा गया है, 14 जुलाई को उनका वजन 61.5 किलोग्राम था। इसलिए प्रभावी रूप से उनका वजन दो किलोग्राम कम हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल जेल में घर का बना खाना खा रहे हैं लेकिन नियमित रूप से अपने भोजन का

कुछ हिस्सा वापस कर देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एम्स का एक चिकित्सा बोर्ड लगातार मुख्यमंत्री की निगरानी कर रहा है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बोर्ड के साथ नियमित संपर्क में हैं। इसमें कहा गया है, आरोपी के रक्तचाप और शर्करा के स्तर तथा वजन की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और उन्हें उनकी सभी बीमारियों के लिए पर्याप्त उपचार प्रदान किया जा रहा है। उन्हें नियमित रूप से दिन में तीन बार घर का बना खाना दिया जा रहा है। निहित स्वार्थी समूहों द्वारा मीडिया में की जा रही बदनामी को देखते हुए ये तथ्य रिकॉर्ड में लाए गए हैं। इस बीच आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा 'लीक' की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि केजरीवाल का वजन कम हो गया और उन्हें जेल में कई बार 'हाइपोग्लाइसीमिया' (रक्त शर्करा के कम होने की समस्या) का सामना करना पड़ा जिसके कारण 'कुछ अप्रिय' घटित हो सकता है। 'आप' सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा केजरीवाल की जान से खेल रही है। उन्होंने कहा कि किसी की मेडिकल रिपोर्ट 'लीक' करना अपराध है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बयान में संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने भी माना कि केजरीवाल के रक्त में शर्करा का स्तर कई बार गिरा है और उनका वजन भी कम हुआ है। उन्होंने दावा किया कि 'आप' प्रमुख के रक्त शर्करा का स्तर पांच मौकों पर रात में 50 मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर से कम हो चुका है और किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है, वह (केजरीवाल) कोमा में जा सकते हैं।

बता दें कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति (अब रद्द हो चुकी) 2021-22 में अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 जून को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 28 जून को उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई के मामले में वह अब भी जेल में हैं। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोप लगाया है कि न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें दी जा रही भोजन की चिकित्सकीय खुराक और दवाएं संभवत: जानबूझकर नहीं ले रहे। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब? उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा जानबूझकर कम कैलोरी लिए जाने के कई उदाहरण हैं, जबकि उन्हें घर का बना खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि सक्सेना ने जेल प्राधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे मुख्यमंत्री को निर्धारित आहार के अलावा दवा

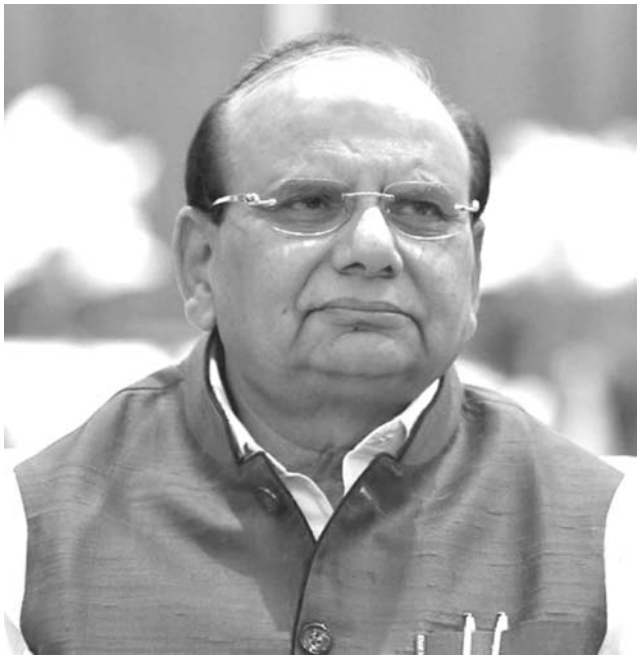

और इंसुलिन की तय खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल 'टाइप-2' मधुमेह से पीड़ित हैं। वही आम आदमी पार्टी ने भाजपा और उसकी अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जेल में बंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को स्थायी नुकसान पहुंचाने की 'साजिश' रचने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि आप प्रमुख का वजन कम हो गया है तथा उनके रक्त शर्करा स्तर में गिरावट आई है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल कोमा में भी जा सकते हैं और उनके मस्तिष्क को भी क्षति हो सकती है, क्योंकि उनका रक्त शर्करा स्तर एक रात में 5 बार 50 मिलीग्राम/डीएल तक गिर गया था। सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि अगर उन्हें जल्द जेल से बाहर नहीं लाया गया और इलाज नहीं किया गया तो उनके साथ कोई भी गंभीर घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि जब 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तब उनका वजन 70 किलोग्राम था, जो कम होकर 61.5 किलोग्राम रह गया है। उनका वजन लगातार घटने का कारण अज्ञात है, क्योंकि कोई जांच नहीं हुई है। वजन घटना किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। आप सांसद ने कहा कि केजरीवाल का परिवार, 'आप' और उनके शुभचिंतक जेल में उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भाजपा और केंद्र की उसकी सरकार का मकसद उन्हें जेल में रखना और उनके जीवन से खेलना है। वे साजिश रच रहे हैं ताकि उन्हें कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण वह अभी भी जेल में हैं। दूसरी ओर उपराज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र के अनुसार, आहार निगरानी चार्ट से पता चलता है कि छह जून से 13 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री ने दिन में तीन बार आहार के लिए निर्धारित पूरी खुराक का सेवन नहीं किया। पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट में वजन में कमी (आत्मसमर्पण की तिथि 2 जून, 2024 को वजन 63.5 किलोग्राम था लेकिन अब 61.5 किलोग्राम रह गया है) का भी संकेत मिलता है। प्रथम दृष्टया, इसका कारण कम कैलोरी सेवन प्रतीत होता है। इसमें कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 18 जून को उन्हें इंसुलिन नहीं दिया गया था या जेल प्राधिकारियों ने रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया था। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि अधिकतर दिनों में 'ग्लूकोमीटर' जांच की रीडिंग और लगातार ग्लूकोज निगरानी तंत्र (सीजीएमएस) की रीडिंग के बीच भी काफी अंतर हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के भोजन से पहले केजरीवाल की 'ग्लूकोमीटर रीडिंग' 104 एमजीएल थी, जबकि 19 जून को दोपहर साढ़े 12 बजे दोपहर के भोजन से पहले 'सीजीएमएस रीडिंग' 82 एमजीएल थी। उसने कहा कि ग्लूकोमीटर जांच रीडिंग और सीजीएमएस रीडिंग के बीच स्पष्ट अंतर को सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 6 जुलाई को तीनों समय निर्धारित आहार नहीं लिया और उन्हें नाश्ते से पहले 5 यूनिट इंसुलिन, दोपहर के भोजन से पहले 4 यूनिट और रात के खाने से पहले 2 यूनिट इंसुलिन दी गई। जेल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि 7 जुलाई को फिर से निर्धारित खुराक नहीं ली गई और उस दिन नाश्ते से पहले 5 यूनिट और दोपहर के भोजन से पहले चार यूनिट इंसुलिन दी गई तथा 'मुख्यमंत्री ने रात के खाने से पहले इंसुलिन लेने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि 'ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब? क्या कोई आदमी खुद की रात में शुगर कम करेगा? जो कि बहुत खतरनाक है। एलजी साहब बीमारी के बारे में पता नहीं तो आपको ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए। ईश्वर ना करें कभी आप के साथ ऐसा समय आए।'

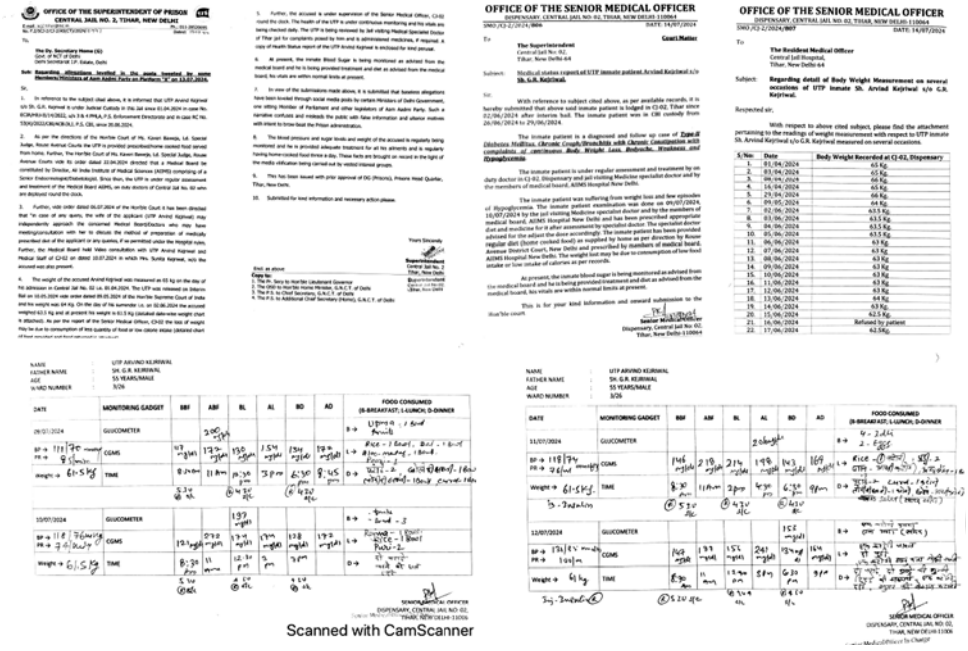

Can India's new budget tackle growing job crisis?

Job creation has emerged as a major test for Indian Prime Minister Narendra Modi's third term, as India's young workforce struggles to find employment. Last year, India overtook China as the world's most populous country, with more than 40% of the estimated population of 1.4 billion younger than 25 years old. Joblessness was a significant factor behind Modi and his Bharatiya Janata Party (BJP) performing below expectations and falling short of an overall majority in India's general elections. As India's government announced its 2024 budget on Tuesday, it earmarked $24 billion over five years to foster job creation. "In this budget, we particularly focus on employment, skilling, small businesses, and the middle class," Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Tuesday. In the budget, Finance Minister Sitharaman announced that the government will launch a scheme to provide internship opportunities to 10 million youth in 500 top companies over five years. Reacting to the budget in a series of tweets, opposition Congress party General Secretary, Jairam Ramesh criticized the BJP government.

"After ten years of denial … the union government seems to have finally come around to tacitly admitting that mass unemployment is a national crisis that requires urgent attention." "It's far too late, and as it turns out, far too little – the budget speech is more focused on posturing than action," added Ramesh. Shrijay Sheth, founder of LegalWiz, a consultancy firm, told DW, that he expects "larger incentives given to companies to choose India for obvious cost benefits and access to a large young workforce, along with preferential access to Indian markets." "This is significant. Hyundai eying an Indian IPO, or talks with Tesla to establish Indian manufacturing with production are indicative examples," added Sheth.

India's growing job crisis

In Mumbai last week, a job event at Air India Airport Services was called off after 25,000 jobseekers showed up to apply for 2,220 maintenance jobs. In February, nearly 4.7 million applicants appeared for an exam to select around 60,000 police constables in the northern state of Uttar Pradesh. These are not isolated incidents as India faces a growing unemployment crisis. "The government and all its agencies are living in denial about unemployment," Arun Kumar, an economist, told DW. "All ground reports and data suggest that unemployment is a major issue where youth are struggling to get work," he added. According to the latest data from the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), an independent think tank, India's unemployment rate came in at 9.2% in June, a sharp increase from 7 % in May this year. "All this is contrary to the official [government] narrative of massive employment generation. Why not admit the problem and act, lest the growing youth frustration boil over?" added Kumar.

Economic growth not leading to jobs

India's government is predicting a GDP growth rate of between 6.5% and 7% for the 2024 fiscal year, after seeing 8.2% expansion in the previous fiscal year that ended in March. Despite these strong numbers, India has struggled to generate enough jobs for the millions of young people entering the labor market every year. Development economist Santosh Mehrotra told DW that India needs to develop a labor-intensive manufacturing strategy similar to China's. "In India, the demand for jobs will only be met if several different factors come together. Construction activity needs to continue at its current brisk pace. But, for the next year or two, it must be led by public sector investment, as private investment remains sluggish," said Mehrotra, a visiting professor at the Centre for Development Studies, University of Bath, England. According to World Bank data, India's manufacturing sector comprises 13% of GDP. In China, manufacturing is over a quarter of GDP. He added that labor-intensive manufacturing by small and medium enterprises (MSME) require a sustained support, through development programs fostering MSME manufacturing,

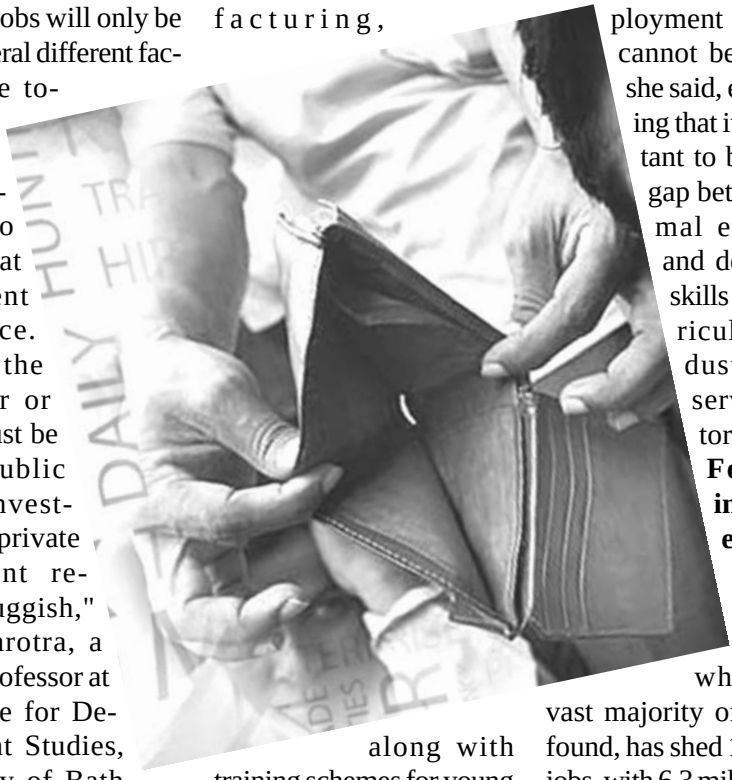

along with training schemes for young people. "A right to apprenticeship is essential," he added. Lekha Chakraborty, a professor at National Institute of Public Finance and Policy said that training programs are essential to solving unemployment.

The labor market is dynamic and unless we prepare the youth with required skills, unemployment problems cannot be solved," she said, emphasizing that it is important to bridge the gap between formal education and developing skills across agriculture, industrial and service sectors.

Formalizing India's economy

India's informal sector, where the vast majority of jobs are found, has shed 16 million jobs, with 6.3 million informal sector enterprises shutting down between the financial years 2016 and 2023, according to a report by credit markets rating agency, India Ratings

An informal economy comprises unincorporated enterprises owned by households, or jobs that are not officially taxed or monitored, and include domestic workers, street vendors and day laborers. "This period also coincided with the rise in the formalization of the economy, which has led to robust tax collections. While formalization of the economy is the way forward, the reduced unorganized sector footprint has implications for employment generation," said Sunil Kumar Sinha, the principal economist of India Ratings.

The finance minister said Tuesday the government's budget will implement schemes for employment incentives, including providing a month's wage to new entrants to workforce in all formal sectors. The scheme aims to create jobs in the manufacturing sector by incentivizing the hiring of first-time employees.

यूपी बीजेपी में रार!

● **समीरात्मज मिश्र**

उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं, योगी बनाम केशव के उस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है जिसकी शुरुआत साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पहले शुरू हुई थी। लोकसभा चुनाव में 303 सीटों से खिसक कर 240 सीटों पर पहुंचने के बाद पार्टी की हार की समीक्षा हो रही है लेकिन इन समीक्षा बैठकों के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी के भविष्य को लेकर आशंकाएं सामने आने लगी हैं। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगा। यूपी में 62 सीटों से घटकर वो 33 पर आ गई तो हार की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, इसे लेकर सवाल उठने लगे। दबे स्वर में सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरे में लेने की कोशिश हो रही है क्योंकि चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी सीट से महज डेढ़ लाख वोटों के मार्जिन से जीते हैं और बनारस से लगी तमाम सीटों पर बीजेपी हार गई। तमाम लोग इसके पीछे यूपी सरकार की नीतियों को दोष दे रहे हैं। खासकर, कथित तौर पर बढ़ते भ्रष्टाचार और

राज्य में नौकरशाही के हावी होने और यहां तक कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के उत्पीड़न की वजह से। लखनऊ में हुई बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक के दौरान ये आरोप-प्रत्यारोप सतह पर आ गए। यहां तक कि सहयोगी दलों के नेताओं ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

गौरतलब है कि अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज करने का सवाल उठाया तो राज्य सरकार में मंत्री और निषाद

अनुप्रिया पटेल

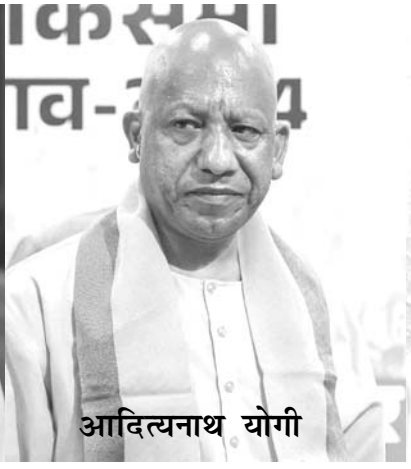
आदित्यनाथ योगी

डॉ. संजय निषाद

पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 'बुलडोजर नीति' को हार का प्रमुख कारण बताया। यही नहीं, कार्यसमिति की बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान खूब छाया रहा कि 'संगठन सरकार से बड़ा होता है।' लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर उनके इस बयान की हवा निकाल दी कि 'सरकार है तभी सब का सम्मान है।' जहां तक बुलडोजर के इस्तेमाल की बात है तो बहुत से ऐसे लोग भी धीरे-धीरे इसकी चपेट में आने लगे जो पहले इसके इस्तेमाल पर तालियां बजाया करते थे। पहले कई मामलों में ज्यादातर बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों के मामलों में हुई तो इसे राजनीतिक तुष्टीकरण से देखा गया लेकिन धीरे-धीरे इसका विस्तार होता गया। हाल ही में लखनऊ में अकबरनगर के पूरे इलाके में बुलडोजर चला दिया गया और सैकड़ों घर जमींदोज कर दिए गए। इससे पहले भी कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं। किसी अपराध में नाम आ जाने पर भी कथित अवैध निर्माण के नाम पर घर ढहा दिए गए। यहां तक कि अदालत की टिप्पणियों के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी रहा। बीजेपी समर्थक बुलडोजर को सरकार की ताकत के प्रतीक के तौर पर प्रचारित करते रहे लेकिन चुनावी हार और खराब प्रदर्शन के बाद अब इसे भी हार के प्रमुख कारणों में गिना जा रहा है। यही नहीं, शायद अब सरकार को भी यह पता चल रहा है कि विध्वंसक कार्रवाइयां ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली हैं। हाल ही में लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे रिवर फ्रंट से जुड़ी योजना को लेकर सैकड़ों घरों को फिर चिह्नित किया गया और ढहाने की तैयारी की जा रही थी लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आश्वासन दिया निजी जमीनों पर बने घर नहीं गिराए जाएंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि बड़ी संख्या में गिराए जा रहे घरों के मामले में यह बड़ा सवाल भी आया कि आखिर सालों से ये घर बनते कैसे चले गए। मुख्यमंत्री के रुख में आए इस बदलाव को भी चुनावी नतीजों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ल कहते हैं, 'निश्चित तौर पर इस तरह के फैसले सरकार के खिलाफ जाते हैं। मकान वैध-अवैध कैसे हैं, ये तय करने का काम किसका है। तमाम विभागों में फैले भ्रष्टाचार के चलते सालों-साल ऐसे मकान बनते रहे तो इन्हें देखने की, जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अब अचानक बुलडोजर चलाकर गिरा

दें गे तो लोग कहां जाएंगे?' शुक्ल का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी ने इस खतरे को भांप लिया है कि सरकार को राजनीतिक फायदा और लोगों की नजरों में सहानुभूति तब बढ़ेगी जब ऐसी कॉलोनियों को बनने देने के दोषियों को पकड़कर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। लोकसभा चुनाव तो केंद्र सरकार के काम-काज की परीक्षा थी, जबकि यूपी सरकार के काम की परीक्षा तो 2027 में होगी जब विधान सभा चुनाव होंगे। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान को जिस तरह आम कार्यकर्ताओं की आवाज के तौर पर प्रचारित किया गया और फिर उनका दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और दूसरे नेताओं से मुलाकात को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि यूपी में योगी बनाम मोदी-शाह की लड़ाई एक बार फिर सतह पर आ गई है। चुनाव से पहले भी टिकट वितरण को लेकर योगी की नाराजगी की काफी चर्चा थी। केशव मौर्य जो भी बयान दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व की सहमति बताई जा रही है। ज्ञानेंद्र शुक्ल कहते हैं, 'खेमेबाजी और खींचतान बीजेपी में चलती रहती है। कल्याण सिंह के समय में भी ऐसा होता था। हालांकि इन चीजों के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं और यदि इस समय भी ऐसा हो रहा है तो जाहिर है यह पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है

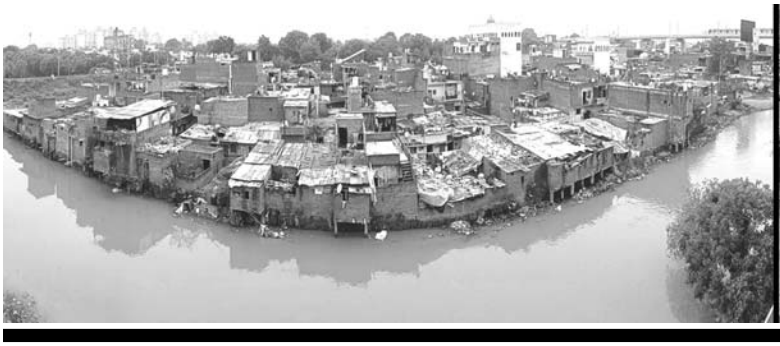

लेकिन वो स्थिति दोहराती हुई दिखाई दे रही है।'

ज्ञात हो कि केशव की नाराजगी तो पहले से ही थी। 2017 के चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके समर्थक मानते थे कि उनकी बड़ी भूमिका थी पार्टी को जिताने और सरकार बनवाने में। हालांकि उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी बड़ी भूमिका रही थी 2014 में लोकसभा में 72 सीटें दिलाने में। लेकिन दोनों ही नेता नेपथ्य में डाल दिए गए। 2017 से 2022 तक भी खींचतान दिखाई दे रही थी। पार्टी के सौ से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे। लेकिन 2022 में जब योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बन गई, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव भी हार गए तो स्थितियां बदल गईं। हालांकि केशव के समर्थक सीधे तौर पर आरोप लगाते रहे कि उन्हें हराया गया। योगी की भूमिका पर भी सवाल उठे लेकिन नेताओं- कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बावजूद नतीजे अच्छे आ रहे थे तो योगी का दबदबा बना रहा। पर अब जबकि 2024 में नतीजे ठीक नहीं आए हैं तो सवाल योगी पर भी उठ रहे हैं। यूपी में बीजेपी सरकार पर जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं और जिसे हार के प्रमुख कारणों में से एक गिना जा रहा है वो है- बेलगाम नौकरशाही। पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से लेकर एमपी और एमएलए तक ये आरोप लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई नेताओं ने तो खुले तौर पर ये बातें कही हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ल भी इसे हार के प्रमुख कारणों में बताते हैं, 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफसरों से पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और देखा जाए तो ये बीजेपी की सरकारों का तरीका भी रहा है-नौकरशाही पर निर्भरता। एक तरह से इसे गुजरात मॉडल भी कह सकते हैं।

पहले भी लोग शिकायत करते थे। कोई अभी की बात नहीं है। विधायक जब धरने पर बैठे थे तब भी सबसे बड़ा आरोप यही था कि नौकरशाही हावी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक हार का ठीकरा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के सिर पर फोड़ने के मूड में हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ परिवार भी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 'अति आत्मविश्वास' हार के प्रमुख कारणों में से रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, यह अति आत्म विश्वास सीधे तौर पर उस जगह निशाना लगा रहा है जहां से एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनी और जिस एक चेहरे पर लड़ने का फैसला हुआ। ऐसी स्थिति में यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना तो फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है लेकिन सरकार और संगठन में बदलाव के संकेत जरूर मिल रहे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ल के मुताबिक, कोई बड़े बदलाव की उम्मीद तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पक्ष में लोकसभा चुनाव के नतीजे होते तो कुछ हो भी सकता था लेकिन इस समय तो केंद्र में भी मजबूत सरकार नहीं है। इसलिए सरकार के स्तर पर तो नहीं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर शायद बदलाव हो। दूसरे, बीजेपी के पास संघ और सहयोगियों के चहेते के रूप में फिलहाल योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प भी नहीं है।

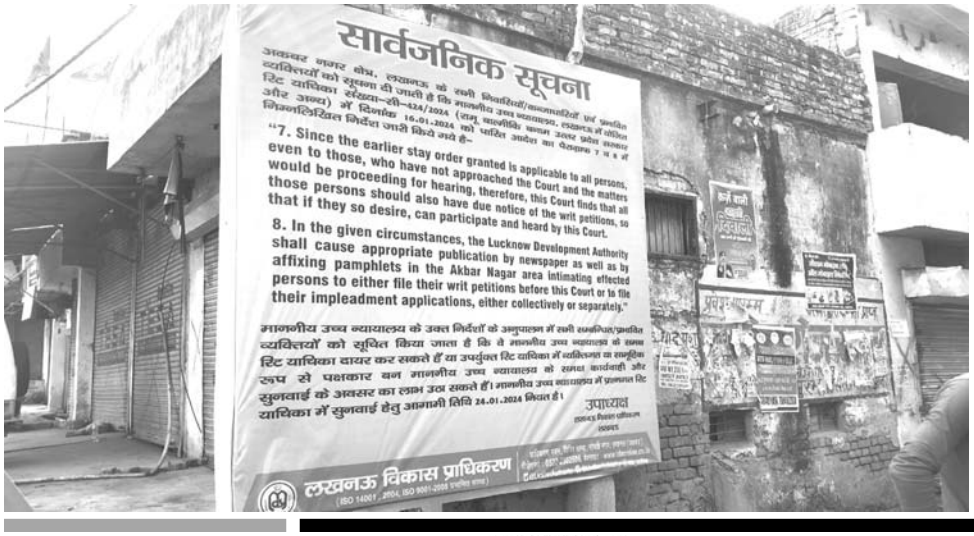

कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद

● अमित कुमार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन माह में निकलने वाली कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने राज्य में निकलने वाली कावड़ यात्रा के मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर 'नेमप्लेट' लगाने के आदेश दिए हैं। इसमें दुकान मालिक का नाम और पता भी लिखने को कहा गया है। यूपी सीएमओ द्वारा जारी बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर 'नेमप्लेट' लगानी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया था, ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। विपक्षी दल इस आदेश को समुदाय विशेष के व्यापारियों को निशाना बनाने के प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के मद्देनजर भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नकवी ने यह भी कहा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है, ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। विपक्षी दल इस आदेश को समुदाय विशेष के व्यापारियों को निशाना बनाने के प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, कुछ अति उत्साही अधिकारियों

मुख्तार अब्बास नकवी

के आदेश हड़बड़ी में गडबड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं, आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। ''जन्म, जात मत पूछिए, का जात अरु पात। रैदास पूत सब प्रभु के, कोए नहिं जात कुजात।'' इस पर जब कुछ लोगों ने उन्हें 'ट्रोल' करने का प्रयास किया तो उन्होंने एक और पोस्ट किया, अरे ट्रोलर टट्टुओं, कावड़ यात्रा के सम्मान, श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो, मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता, अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। नकवी ने अपनी एक पुरानी तस्वीर भी साझा की, जिसमें वे अपने कंधे पर कावड़ लिए हुए नजर आ रहे हैं। वही भाजपा के सहयोगी रालोद नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने एक बड़ा बयान देते हुए योगी सरकार के कावड़ यात्रा मार्ग पर खानपान की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने संबंधी आदेश पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कावड़िए जाति धर्म देखकर सेवा नहीं लेते। लोकसभा चुनाव से पहले सपा का साथ छोड़कर भाजपा से गठबंधन करने वाले उन्होंने

फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कावड़ यात्रियों की सेवा सब करते हैं। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भाजपा ने ज्यादा समझकर यह फैसला नहीं लिया है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों और ठेलेवालों के लिए अपनी दुकानों और ठेलों पर नेमप्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी फैसला लागू हो गया। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कई भाजपा नेताओं ने ढाबा और रेस्त्रां पर मालिक का नाम लिखने की मांग की है।

जयंत चौधरी

इंदौर के 2 विधायकों रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। बहरहाल रालोद के साथ ही जदयू और एलजेपी भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसले से खुश नहीं है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने साफ कर दिया है कि यह फैसला राज्य में लागू नहीं होगा। सनद् रहे कि कावड़ यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। वही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए जारी किए गए परामर्श को लेकर भाजपा नीत उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में लिखित आदेश जारी करने की चुनौती दी। हैदराबाद के सांसद ने इसे स्पष्ट रूप से 'भेदभावपूर्ण' आदेश करार दिया और आरोप लगाया कि यह दर्शाता है कि सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुसलमानों को 'दूसरे दर्जे' का नागरिक बनाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि हम इसकी (मौखिक

आदेश की) निंदा करते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, जिसमें अस्पृश्यता की बात कही गई है। ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही है। आदेश दिए जाने के बाद से मुजफ्फरनगर में ढाबों के मालिकों ने मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया है। यह मुसलमानों के साथ स्पष्ट भेदभाव है। संविधान की भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है। यह जीवन के अधिकार और आजीविका के अधिकार के खिलाफ है। एआईएमआईएम प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह इस पर लिखित आदेश जारी करें। भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमानों के प्रति नफरत रखने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने दावा किया कि वे लगातार हिंदुत्व की विचारधारा को लागू कर रहे हैं और यह उनकी बड़ी 'योजना' का कार्यान्वयन है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से हिंदुत्ववादी संगठन मुसलमानों के 'सामाजिक बहिष्कार' का आह्वान कर रहे हैं और अब यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने

मुजफ्फरनगर पुलिस

श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान समीपवर्ती राज्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए भारी संख्या में काँवड़िये हरिद्वार से जल उठाकर मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र माह में कई लोग खासकर काँवड़िये अपने खानपान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज़ करते हैं। पूर्व मे ऐसे दृष्टान्त प्रकाश मे आये हैं जहा कांवड़ मार्ग पर हर प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारो द्वारा अपनी दुकानो के नाम इस प्रकार से रखे गए जिससे कांवड़ियो मे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने एव श्रद्धालुओ की आस्था के दृष्टिगत कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे एव खानपान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। इस आदेश का आशय किसी प्रकार का धार्मिक विभेद ना होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है। यह व्यवस्था पूर्व मे भी प्रचलित रही है।

श्रद्धालुओं के बीच किसी भी 'भ्रम' से बचने के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी ढाबों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। विपक्षी दलों ने इस कदम को मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा है। वही असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की इस टिप्पणी पर कि असम में मुस्लिम आबादी अब 40 प्रतिशत हो गई है, ओवैसी ने उन्हें देश के शीर्ष पांच झूठ बोलने वालों में से एक बताया। ओवैसी ने कहा, असम के मुख्यमंत्री भारत के शीर्ष पांच झूठ बोलने वालों में से एक हैं। सच्चाई यह है कि 1951 में असम में मुस्लिम आबादी 24.68 प्रतिशत थी। वह झूठे हैं और असम के मुसलमानों से नफरत करते हैं। ओवैसी ने कहा, 2001 में मुस्लिम आबादी 30.92 प्रतिशत थी और 2011 की जनगणना में यह 34.22 प्रतिशत थी। अब 2024 में यह 40 प्रतिशत हो सकती है, तो क्या हुआ? उनके झूठ के कारण पूरा प्रशासन मुसलमानों से नफरत कर रहा है। शर्मा ने कहा था कि जनसांख्यिकी परिवर्तन असम में एक बड़ा मुद्दा है। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर असम में 40 प्रतिशत मुसलमान हैं तो इसमें असंवैधानिक क्या है? उन्होंने पूछा कि यह जीवन और मृत्यु का मामला कैसे बन गया है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को एक विशेष समुदाय से नफरत करने के लिए शर्म आनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, आप अल्पसंख्यकों को क्या संदेश दे रहे हैं? आप इस आबादी को लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं? वे भारतीय हैं। राजनीतिक रूप से आपको हारना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप असम में बुरी तरह हारेंगे और आपकी पार्टी असम में खत्म हो जाएगी। आपको 40 प्रतिशत मुसलमानों को निशाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 'सबका साथ, सबका विकास' अनावश्यक है, इसके बजाय 'हम उनके साथ जो हमारे साथ हैं', होना चाहिए। अधिकारी के इस बयान पर ओवैसी ने कहा कि भाजपा नफरत व्यक्त कर रही है और अब उनकी नफरत खुले तौर पर सामने आ रही है। ओवैसी ने कहा कि यह भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री हैं जो इस बकवास राजनीति में लिप्त हैं, जो खुलेआम सामाजिक बहिष्कार की बात कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान देश के लिए खतरा हैं और यह उनकी भेदभाव और घृणा की नीति

असदुद्दीन ओवैसी

अखिलेश यादव

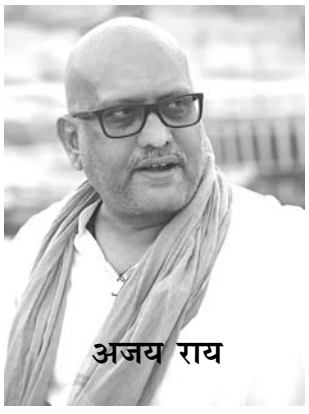
अजय राय

दिखाता है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के एक आदेश पर सख्त नाराजगी जताई है। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के उस आदेश को सामाजिक अपराध करार दिया, जिसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों से उनके मालिकों का नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है। उन्होंने अदालतों से मामले का स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया। आदेश को लेकर एक अखबार में प्रकाशित खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि'...और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय स्वत: संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर, उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं।' मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रमुख अभिषेक सिंह ने एक आदेश में कहा कि जिले में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां लगभग 240 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग है। मार्ग पर स्थित सभी होटल, ढाबे, ठेले वालों से अपने मालिकों या फिर वहां काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। यह इसलिए जरूरी है, ताकि किसी कांवड़ियों के मन में कोई भ्रम न रहे। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा कावड़ यात्रा मार्ग पर खानपान की दुकानों पर नेम प्लेट संबंधी आदेश पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। यूपी सीएमओ द्वारा जारी बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर श्नेमप्लेटश लगानी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आदेश पर सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने नाराजगी जताते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर नाराजगी जताई और आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 'यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णत: असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकाट करने का प्रयास अति-निन्दनीय है।'

गौरतलब है कि योगी सरकार के आदेश पर जहां सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं मध्यप्रदेश में इस तरह की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा नेता धैर्यवर्धन ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तरह अब मध्य प्रदेश में भी दुकानदारों को अपना नाम और पता लिखने को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य धैर्यवर्धन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की है कि खाद्य सामग्री विक्रेताओं की दुकान, हाथ ठेलों पर अनिवार्य रूप से नाम, आधार कार्ड पर अंकित पता और गुमास्ता कानून के अंतर्गत आवंटित पंजीयन नंबर और विक्रेता तथा दुकान मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्यत: लिखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि गुमास्ता कानून के पालनार्थ भी सभी

मोहन यादव

मायावती

विक्रेताओं को अपना नाम और पता दुकान पर साफ, बड़े अक्षरों में लिखना ही चाहिए। भाजपा नेता धैर्यवर्धन ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तरह अब मध्य प्रदेश में भी इसे अनिवार्यत: लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार विक्रेताओं द्वारा अमानक और अशुद्ध सामग्री बेच दी जाती है। खरीददारों को यह भी पता नहीं होता कि उसको गलत, अशुद्ध या सड़ी, गली सामग्री देने वाला दुकानदार कौन है। नगर पालिका कुछ समय पूर्व जब गली-गली में मौजूद रेहड़ी, ठेले वालों से प्रतिदिन टैक्स वसूली करती थी तो उनका नाम, पता लिखने में एतराज क्यों! नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम आदि संस्थाओं को इस सभी विक्रेताओं को एक विक्रेता नंबर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि नगर पालिका में टैक्स की राशि ज्यादा पहुंचेगी। जब मध्य प्रदेश में हाथ ठेला वालों से प्रतिदिन पैसे लेने की प्रथा थी तब ठेकेदार या वसूली कर्मचारी बड़ी तादाद में दुकानदारों से सड़क पर खड़े होने के एवज में पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लेते हैं। खान पान का सामान बेचने वाले और जिम्मेदार बने इसलिए खान-पान की रेहड़ी वाले जरूर यह जानकारी स्वप्रेरणा से पठनीय आकर में यह सब लिखें। वही 22 जुलाई से श्रावण मास की कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। करोड़ों की संख्या में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के कावड़िये आस्था के सरोवर में डुबकी लगाकर नंगे पैर हरिद्वार से गंगा जल कंधे पर रखकर शिवालयों

की तरफ कूच करते हैं। कई राज्यों के शिवभक्त उत्तरप्रदेश से गुजरकर उत्तराखंड में गंगा जल लेने आते हैं। पैदल सैकड़ों मीलों का सफर करने में कई दिन-रात लग जाते हैं। ऐसे में कावड़ियों के जत्थे रास्ते में धर्मशाला, सड़कों के किनारे लगे शिविरों में रुकते हैं। मार्ग में पड़ने वाले ढाबों-होटलों पर खाते-पीते हैं। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के हाईवे पर बहुत से रेस्टॉरेंट, ढाबे, रेडी और दुकानें हैं जिनका नाम हिन्दू धर्म पर आधारित है लेकिन उसे मुसलमान संचालित करते हैं। ऐसे मुसलमानों को अपनी पहचान यूपी और उत्तराखंड में उजागर करनी होगी, वहीं संत समाज ने इस निर्णय का स्वागत किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएम ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने के लिए नाम का खुलासा करना होगा। जब यह आदेश दिया तो राजनीतिक माहौल गरमा गया। चारों तरफ चर्चा होने लगी कि धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, रोजगार पर चोट की जा रही है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। व्यापारी तबके को बोर्ड लगाकर अपने नाम को उजागर करना पड़ रहा है, हालांकि धार्मिक कावड़ यात्रा वर्षों से इन्हीं मार्गों से होकर गुजरती रही है। मुजफ्फरनगर प्रशासन का कहना है कि 240 किलोमीटर का कावड़ मार्ग उनके जिले

से होकर गुजरता है जिसके चलते किसी भी तरह की दो धर्मों के बीच में गलतफहमी की वजह से मनमुटाव और संघर्ष न हो, उसके लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं हिन्दू ढाबों, रेस्टॉरेंट पर काम करने वाले मुसलमानों का रोजगार भी छिन गया। होटल मालिक ने मुस्लिम काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में बेरोजगारी कम होने की जगह बढ़ जाएगी और नफरत की खाई दिखाई देने लगेगी। वहीं खाद्य सामग्री विक्रेताओं ने प्रतिष्ठान के बाहर और रेडी पर नाम के बोर्ड चस्पा कर दिए हैं। मुस्लिम समाज में रोष पनपना शुरू हो गया है जिसके चलते टायर-पंक्चर लगाने वालों ने भी अपने नाम की तख्ती टांग ली है। मुजफ्फरनगर सांसद ने कहा है कि धार्मिक तौर पर भावनाओं को भड़काने का प्रयास है, ऐसा होना गलत है। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा कि आम के खेत व दालों की खेती करने वाला कौन है? कौन उन्हें तोड़ता है, किसके माध्यम सें मंडी में माल आता है, ड्राइवर और उतारने वाले से लेकर बाजार में बेचने वाले कई माध्यम हैं, किस-किस की पहचान होगी? मुजफ्फरनगर में जारी हुए इस फरमान के बाद हरिद्वार प्रशासन ने कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल-ढाबों के सत्यापन के आदेश दे दिए हैं। हरिद्वार में साधु-संतों ने जिसका खुले दिल से स्वागत किया है। देवभूमि के साधु-संतों का कहना है कि उत्तराखंड में धार्मिक जिहाद चल रहा है। होटल-ढाबों के नाम पर मुसलमान व्यापार करके गुमराह कर रहे हैं। ये हिन्दू नाम रख पहचान छुपाते हैं जिससे धार्मिक दर्शन और यात्रा पर आए लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक जिहाद को खत्म

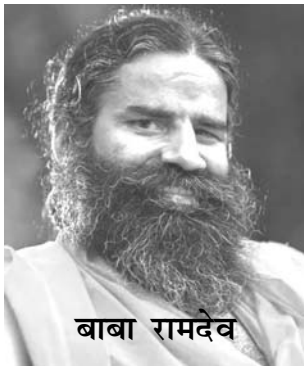
बाबा रामदेव

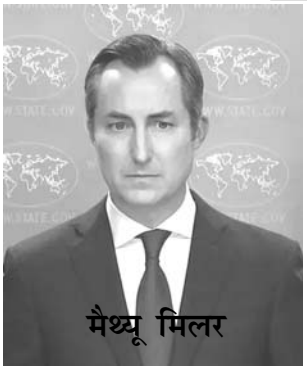
मैथ्यू मिलर

करने के लिए यूपी और उत्तराखंड में जो कार्रवाई हो रही है, वह स्वागतयोग्य है। संत-महात्माओं का कहना है कि पहले भी कावड़ यात्रा के दौरान ढाबों के नाम बदलकर संचालित होने की घटनाएं सामने आई हैं जिससे यहां का माहौल खराब हुआ, इसलिए हरिद्वार में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर पहचान छुपाकर होटल-ढाबा कारोबारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसी बीच योगगुरु बाबा रामदेव ने कावड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट विवाद में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामदेव पहचान बता सकता है तो रहमान को दिक्कत क्यों? रामदेव ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश के समर्थन करते हुए कहा कि हमें अपनी पहचान उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं खुद को रामदेव के रूप में अपनी पहचान सबके सामने उजागर करता हूं, तो रहमान को अपनी पहचान सभी के सामने में लाने में क्यों दिक्कत है? बाबा ने कहा कि अपने नाम पर गौरव सबको होता है। नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, काम में शुद्धता चाहिए बस। सभी धर्म के लोगों को अपना पर्व और उत्सव अपने हिसाब से मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। नेम प्लेट मामले में विरोध की कोई वजह नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग में आने वाली खान पान की दुकानों के मालिकों से नेमप्लेट लगाकर उसमें अपना नाम लिखने को कहा है। आदेश पर बवाल मच गया। विपक्ष ने मामले पर कड़ी नाराजगी जताई वहीं मुस्लिम पक्ष इस मामले में कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति करार दिया। वहीं भाजपा का कहना है कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का वैसे ही पूरा हक है, जैसे अन्य धर्मों के लोगों को।

बहरहाल, कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट का मामला अमेरिका तक पहुंच चुका है। बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस वार्ता में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत में कावड़ यात्रा के दौरान नेमप्लेट पर नाम लिखने का मामला उठाया। इस पर इस पर विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब भी दिया। मिलर ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्गों में भोजनालयों पर नेमप्लेट के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है इसलिए अब वो वास्तव में प्रभावी नहीं हैं जिसपर सवाल उठाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी रिपोर्ट भी देखी हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उन नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक जारी की है। इसलिए वे वास्तव में प्रभावी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने आदेश दिया था कि कावड़ यात्रा के रूट पर सभी खाने-पीने की दुकाने के आगे मालिक अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का आदेश पारित किया। मध्यप्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में भी इस आदेश को लागू करने की मांग की गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने नेमप्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी।

Kargil Vijay Diwas 2024

PM Modi pays homage to Kargil war heroes in Drass, inaugurates Shinkun La tunnel project

Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the heroes of the Kargil War at Kargil War Memorial on the occasion of 25th Kargil Vijay Diwas. The victory of the Indian Army over Pakistan in Kargil war in 1999 is celebrated as Vijay Diwas. In 1999, Pakistani soldiers and militants from many groups had occupied several peaks from Drass to Batalik sector along the Line of Control (LoC) overlooking the strategic Srinagar-Leh highway. The Indian Army along with the Indian Air Force later launched a massive operation and in the 74 days of battles the Indian Army managed to win back its territory. And since then the Army has been observing July 26 as Vijay Diwas and the main function is held in Drass. The three-day grand celebrations to mark the 'Rajat Jyanti' of India's victory over Pakistan in the 1999 war began at Drass in Kargil district on Wednesday. During the visit, the Prime Minister also carried out the first blast of the Shinkun La Tunnel Project, virtually. Shinkun La Tunnel Project consists of a 4.1 km long Twin-Tube tunnel which will be constructed at an altitude of around 15,800 feet on the Nimu – Padum – Darcha Road to provide all weather connectivity to Leh. Once completed, it will be the highest tunnel in the world. Shinkun La tunnel will not only ensure swift and efficient movement of our armed forces and equipment but also foster economic and social development in Ladakh.

☞ **Kargil Vijay Diwas: PM Modi says Pakistan keeps itself relevant through terrorism & proxy war, defends Agnipath scheme :-** Prime Minister Narendra Modi on Friday said that Pakistan had not learned any lessons from past defeats and mistakes and is trying to keep itself "relevant with the help of terrorism and proxy war". Modi also defended the

Capt. Vikram Batra : The poster boy of Kargil war was invincible for Pak Rangers

Vikram is very popular in Pakistan too. -The Pakistani Army used to call him Sher Shah.

When Vikram Batra used to lash on to the enemies, he used to tell fellow soldiers that you stay aside as you have a wife and children to take care of. In the Kargil War, Vikram unfurled the tricolor on the peaks one by one and said 'Yeh Dil mange More'This punch line of advertisment was resonated as the voice of the army in the whole country during the Kargil War. It was the Midnight of 20 June 1999, When more than half of India's population was fast asleep. Thousands of feet above sea level, the snow-capped mountains were buzzing with sounds of ammunition and mortar. Amid snow, the Soldiers were covered with smoke of the ammunition. These ghats were trembled by the slogans of Bharat Mata ki Jai and Indian Army Zindabad. In fact, the soldiers of the Indian Army were going all guns blazing to liberate the enemy at a very important peak (5140)on the Srinagar-Leh road.

Captain Vikram Batra the name became popular in the country more than a celebrity while the soldiers were fighting tooth and nail by shootings and bomb blasts carried out by the Pak Rangers. However, the nation remains grateful to every martyr Jawan, But the Velour of Captain Vikram Batra impressed all the citizens. Thus He emerged as the poster boy of the Kargil war stoked between India and Pakistan. In 1996, Vikram Batra was selected in the Indian Military Academy. He rejected a whopping offer of crores to join the Merchant Navy as the goal was to serve the nation, not to mint money. That's not all, he did not let his love interest pose as a hurdle in the way of this patriotism. Vikram was posted as Lieutenant on 13 December 1997 in 13 Jammu and Kashmir Rifles after rigorous training.

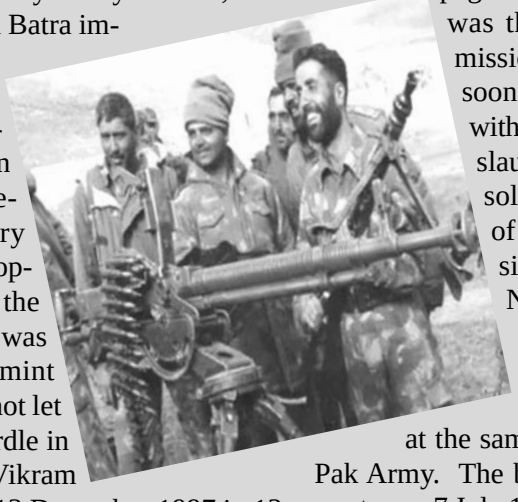

During the Kargil War with Pakistan, his battalion was handed over to win Hamp and Raki Nab peak on 1 June 1999. Vikram and co. managed to achieve both these targets without much ado. Later, Vikram was promoted as the captain. The real mission

before him was to liberate the most important 5140 peaks from the Pak Army just above the Srinagar-Leh road. Extremely Acrobatic and Gallant Vikram Batra, along with his soldiers, took possession of the above peak at 3:30 am on 20 June 1999 and hoisted the tricolor. After witnessing Vikram's valor and caliber, the Indian Army was confident that he would create rampage in Pakistan contingent. Perhaps, This was the reason why he was handed the mission to capture peak 4875 as well. As soon as the mission started, Vikram along with Lieutenant Anuj Nayyar began an onslaught and neutralized many Pakistani soldiers. The mission was on the brink of getting accomplished, but an explosion near Junior Officer Lieutenant Naveen injured both of his legs.

Captain Batra's runs towards Naveen and got hold of him. He starts dragging him back to save and at the same moment a bullet hits his chest by Pak Army. The brave son of Motherland becomes a martyr on 7 July 1999. While unfurling Tricolor on the peak, Vikram Batra and his punch line 'Yeh Dil Maange More', remains immortal even after 21years. Born on 9 September 1974 at the house of GL Batra and Kamalakanta Batra in Palampur, Vikram Batra opted to join the Indian Army after studying in Chandigarh and was laid to rest with full state honors.

Agnipath scheme and termed it a "necessary reform" to make the army young and keep it battle-ready. Modi was addressing a gathering of serving and retired Army officers at the War Memorial in Drass on the 25th anniversary of the Kargil War. The Prime Minister said Pakistan has faced defeat for all its immoral and shameful attempts in the past. "They (Pakistan) have always failed in the past. But Pakistan has not learned anything from its history. It is trying to keep itself relevant with the help of terrorism and proxy war. Today when I am speaking from a place where the masters of terror can hear my voice directly, I want to tell these patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. Our brave hearts (soldiers) will crush terrorism with full force and the enemy will be given a befitting reply," Modi said in his address, in an indirect reference to the heightened terror strikes in Jammu and & Kashmir. Speaking about the 1999 Kargil war, Modi said India not only won the war but gave a wonderful example of 'truth, restraint and strength'. "In Kargil, we not only won the war, but we also gave a wonderful example of 'truth, restraint and strength'. You know, India at that time was trying for peace, and in return, Pakistan once again showed its untrustworthy face. But falsehood and terror were defeated in the face of truth," PM Modi said. The Prime Minister also took a dig at the Congress and its allies in the Opposition over the Agnipath scheme and accused them of "politicisation of the issue". Modi said the goal of Agnipath in the Army is to make the Army young and keep them fit for war.

In a veiled attack on the Congress, which had promised to scrap the Agnipath scheme during Lok Sabha polls, Modi said some people used to think that the Army meant saluting politicians and doing parades. "But for us, the Army means the faith of 140 crore countrymen. The goal of Agnipath is to make the Army young, to keep the Army continuously fit for war. Unfortunately, some people have made such a sensitive issue related to national security a subject of politics. These are the same people who weakened our Army by committing scams worth thousands of crore," said PM Modi. Without naming any Opposition party, Modi said that these are the same people who wanted the Indian Air Force to never get a modern fighter jet. "These are the same people who had made preparations to scrap the Tejas fighter plane," the PM said. "The truth is that the Agnipath scheme will strengthen the nation."

The PM said some people are spreading myths that the government has brought the Agnipath scheme to save pension costs. "The pension burden of the soldiers being recruited today will come up after 30 years. Therefore, this cannot be the reason behind the scheme. We have respected this decision taken by the armed forces because for us the security of the country is more important than politics", he added. The Prime Minister pointed out that those misleading the youth of the country today had no regard for the armed forces in the past. "These people allocated Rs 500 crore for one rank one pension and lied about the matter. Our government implemented one rank-one pension and gave ex-soldiers more than Rs 1.25 lakh crore. These are the same people who did not build a war memorial for the martyrs even after seven decades of independence, did not provide enough bulletproof jackets to our soldiers deployed on the border, and kept ignoring Kargil Vijay Diwas," he said.

The PM also talked about the abrogation of Article 370 which granted special status to Jammu and Kashmir. "In a few days, on August 5, it will be 5 years since Article 370 was abolished. Jammu and Kashmir is talking about a new future, talking about big dreams... Along with infrastructure development, the tourism sector is also growing rapidly in Ladakh and Jammu and Kashmir," he said, adding the country will defeat any effort impeding the development of the region. Earlier, the Prime Minister laid a wreath at the Kargil War Memorial in Drass and paid homage to the soldiers who were killed during the war in 1999. PM Modi also carried out the first blast of the Shinkun La Tunnel Project, virtually. Once completed, the tunnel will be the highest in the world.

जिस गैंगस्टर का एनकाउंटर हो गया, उसकी मौत पर आज भी क्यों मचा है बवाल?

● नवीन रंगीयाल

आनंदपाल लिकर किंग बनना चाहता था, जिसके कारण विरोधी गैंग से उसकी लड़ाई होती रहती थी। बीकानेर जेल में 2015 में उसका गैंगवार हुआ था जिसमें उसे भी गोली लगी थी। आनंदपाल राजस्थान के अपराध जगत में हथियारों और खून-खराबे के सहारे पहले नंबर पर आना चाहता था। राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं तहसील के एक छोटे से गांव का रहने वाला आनंदपाल मर्डर, लूट, वसूली और गैंगवार के करीब 24 मामलों में शामिल था। जानते हैं कौन था आनंद पाल जिसकी मौत के इतने सालों बाद आज भी बवाल मचा है।

☞ **आनंदपाल एनकाउंटर में नया मोड़ :** गैंगस्ट्र आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर साल 2017 में हुआ था। लेकिन राजस्थान के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब जाकर एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में अब ACJM सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही संज्ञान लिया है। यह वह पुलिसकर्मी हैं जो आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल थे। वहीं कोर्ट की ओर से CBI की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। जिस पर कोर्ट ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। इसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। बता दें, आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर साल 2017 में हुआ था। जबकि इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था।

☞ **एनकाउंटर को किया था चैलेंज:** दरअसल, आनंदपाल की पत्नी राजकंवर और रुपिंदर सिंह की ओर से वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर को लेकर चौलेंज किया था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही इसमें कोई फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं

आनंद पाल की अपराध की लिस्ट :-

☞ सीकर में हुए गोपाल फोगावट हत्याकांड में भी उसी का हाथ बताया जाता है। ये मामला विधानसभा में उठा था।

☞ जून, 2011 में उसने बीकानेर के सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर गोलीबारी की थी। तीन लोग घायल हुए थे। आरोप था कि उसी दिन उसने गनौड़ा जगह में शराब ठेके पर सेल्समैन के भाई को मार दिया।

☞ पहले वह बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल और उसके साथी सुभाष मूंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था।

☞ आनंदपाल ने लौटते हुए पुलिस वालों को मिठाई खिलाई जिससे उन्हें नशा आ गया। आगे उसके साथियों ने सड़क रोक ली और गोलियां चलाते हुए उसे भगाकर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया था।

होने की बात कही गई थी। हालांकि मौका-ए-वारदात का नक्शा पेश नहीं किये जाने पर कोर्ट ने आदेश दिया था।

☞ **राजपूत नहीं मानते थे आनंद पाल को :** आनंदपाल के गांव के दबंग उसको राजपूत नहीं मानते थे, क्योंकि वो दारोगा यानी रावणा राजपूत था। इस जाति के लोगों को आज भी निचले तबके का माना जाता है। यही कारण था कि जब आनंदपाल की बरात घोड़ी पर निकलने के लिए तैयार हुई तो काफी बवाल हुआ।

☞ **कौन था आनंदपाल:** आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं तहसील के छोटे से गांव का था। जिस पर हत्या, लूट, वसूली और गैंगवार के करीब 24 मामले दर्ज थे। बताया जाता है कि वह अपराध की दुनिया का किंग बनना चाहता था। इस वजह से उसकी विरोधियों के साथ गैंगवार होती रही। बताया जाता है कि साल 2006 में उसने अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। जब उसने डीडवाना में जीवनराम गोदरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सीकर में हुए गोपाल फोगावट हत्याकांड में भी उसका हाथ बताया जाता है।

☞ **2017 में क्या हुआ था सांवराद में :** 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। राजपूत समाज से जुड़े संगठनों ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। एनकाउंटर के बाद आनंदपाल का शव उसके पैतृक गांव सांवराद में लाया गया था और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन परिजनों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था और आनंदपाल का दाह संस्कार करने से मना कर दिया था। करीब तीन सप्ताह तक आनंदपाल के शव को डीप फ्रीजर में रखा गया था। हालांकि, इसके बाद आनंद पाल के शव का दाह संस्कार कर दिया गया था।

☞ **श्रद्धांजलि सभा में भड़की थी हिंसा :** इस घटना के बाद सांवराद में राजपूत समाज के हजारों लोग आनंदपाल को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे थे। देखते ही देखते श्रद्धांजलि सभा हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी भी फूंक दी थी। इसके बाद हिंसा को देखते हुए कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। उग्र लोगों ने सांवराद रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया, बल्कि बुकिंग काउंटर पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की थी। भीड़ ने नागौर के एसपी परिस देशमुख की गाड़ी को भी आग लगा दी। यही नहीं उत्पाती लोगों ने दो पुलिसकर्मियों के हथियार भी छीन लिए। इस दौरान पुलिस की एक महिला अधिकारी लापता हो गई थी, जबकि इस पूरे हुड़दंग में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

UPSC initiates action against trainee IAS officer Pooja Khedkar for fraud, files FIR

The Union Public Service Commission (UPSC) on Friday filed an First Information Report (FIR) against Pooja Khedkar, the trainee IAS officer, besides issuing a show cause notice for cancellation of her candidature of the Civil Services Examination-2022 and also debar her from future examinations. According to an official statement, The UPSC has conducted a detailed and thorough investigation in the misdemeanour of Ms. Pooja Manorama Dilip Khedkar, a provisionally recommended candidate of the Civil Services Examination-2022. From this investigation it has been revealed that she fraudulently availed attempts beyond the permissible limit under the Examination Rules by faking her identity by way of changing her name, her father's and mother's name, her photograph/ signature, her email ID, mobile number and address. The UPSC further said that it has initiated a series of actions against her, including Criminal Prosecution by filing a First Information Report (FIR) with the Police Authorities and has issued a Show Cause Notice (SCN) for cancellation of her candidature of the Civil Services Examination-2022/ debarment from future examinations/ selections, in accordance with the Rules of the Civil Services Examination-2022. "It is categorically stated that in fulfilling its Constitutional obligations, the UPSC stringently adheres to its Constitutional mandate, and conducts all its processes, including all examinations, with the highest possible order of due diligence without any compromise. The UPSC has ensured the sanctity and integrity of all its examination processes with the utmost fairness and strict observance of Rules," the statement said. The UPSC has deservedly earned the trust and credibility of a very high order from the public, especially the candidates. The Commission is unequivocally committed to ensure that such high order of trust and credibility remains intact and uncompromised, the statement added.

Bihar Shocker! VIP party chief Mukesh Sahani's father brutally killed in Darbhanga

In a gruesome incident, father of Vikassheel Insaan Party (VIP) party chief Mukesh Sahani was killed at his ancestral residence under Biraul police station area in Darbhanga district on Tuesday. Senior police superintendent Jagannath Reddy told media persons here on Tuesday that criminals killed Jeetan Sahani, father of VIP chief Mukesh Sahani, at his residence itself, located in Supaul Bazar, under the Afzal Panchayat of Biraul sub-division. A mutilated body was recovered this morning, he informed. "A Special Investigation Team (SIT) has been constituted to crack the case," Reddy said, adding that the SIT would be headed by SP (Rural) Kamya Mishra of Darbhanga. The SDPO of Biraul, the officer-in-charge of Biraul police station, and an officer of the technical cell of Darbhanga police would be members of the SIT, he stated. Senior police officers had already visited the spot after receiving the incident, he informed. Mukesh Sahani, currently in Mumbai, confirmed via phone that he will reach Supaul by late evening due to an unavailable flight for his early return.

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

★ अगर कोई नेता अपने भाषण से विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगों के बीच नफरत पैदा करने वाला कोई बयान या भाषण देता है तो उसके लिए उन पर किस प्रकार के कानूनी बंधन लागू होंगे ?

यदि कोई व्यक्ति चाहे वह नेता हो या आम पब्लिक हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो वह धर्म मूल वंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा इत्यादि के आधारों पर समाज के विभिन्न जाति वर्गों या समूहों के बीच शत्रुता या नफरत एवं सौहार्द के वातावरण को खराब करने के उद्देश्य से अगर कार्य करते हैं तो उनके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में जो वर्णन है उसके अनुसार कोई व्यक्ति जो बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक मूल्य वंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूह जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द, शत्रुता ,घृणा या वह मनुष्य की भावनाएं धर्म मूल वंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर लोगों को भड़काने या उकसाने का प्रयास करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक मूल भाषाई या प्रादेशिक समूह या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोग शांति में विघ्न डालता है या जिससे कार्य से विघ्न होना संभव हो अथवा कोई ऐसा प्रयास आंदोलन कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक मूल वंशीय भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विभिन्न आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक मूल वंशीय भाषा प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध अपराध इकबालिया हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे जिससे समाज में असुरक्षा डर भय की भावना उत्पन्न होती है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (क) के अनुसार 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है द्यचुनाव के वक्त चुनाव आयोग खासकर यह दिशा निर्देश सभी राजनीतिक पार्टियों को देती है कि वह अपने उम्मीदवारों को यह सख्त हिदायत दें कि वह चुनाव प्रचार में ऐसी कोई बात जनता के सामने उनके भावनाओं को भड़काने वाली बात नहीं करेंगे अगर वह ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और उन पर जनप्रतिनिधि अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता में जो अपराध के लिए धाराएं हैं उनके अनुसार उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें दोषी पाए जाने पर दंड का भागीदार भी बनना पड़ेगा।

★ अगर कोई सरकारी सेवक कानून की अवहेलना करता है या अगर कोई पुलिस केस दर्ज करने से मना करता है तो इसके लिए उस सरकारी सेवक पर किस प्रकार का मुकदमा चलेगा?

भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में बतलाया गया है जो कानून के तहत निर्देश की अवहेलना या उल्लंघन करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 उस लोक सेवा या सरकारी कर्मचारियों के लिए सजा का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है , इस धारा के दो भाग और भी हैं जिसमें धारा 166 ए और धारा 166 भी शामिल हैद्य आईपीसी 1860 की धारा 166 ए में उस लोक सेवा या सरकारी कर्मचारियों के बारे में बतलाया गया है जो कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता हैद्य आईपीसी की धारा 166 ए के अनुसार जो कोई लोक सेवक होते हुए:-

(1) विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो किसी अपराध में आवेला के प्रयोजन या किसी अन्य मामले के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थित के अपेक्षा करने से उसे प्रतिसिद्ध करता जानते हुए अवज्ञा करेगा या

(2) उस ढंग को जिस ढंग से वह ऐसे अन्वेषण को संचालित करेगा एवं विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जानते हुए अवज्ञा करेगा या

(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 की उपधारा 1 के अधीन और विशिष्ट रूप से धारा 326 क धारा 326 ख धारा 354 धारा 354 ख धारा 370 धारा 370 क धारा 376 धारा 376 क धारा 376 क धारा 376 ख 376 ग 376 घ 376 घ क 376 घ ख 376 ङ धारा 509 के अधीन दंडनीय संगेय अपराध के संबंध में उसकी दी गई इतिला को अभीलिखित करने में असफल रहेगा वह अपराधी के तौर पर सजा का हकदार होगा।

सजा का प्रावधान :- ऐसी गलती करने वाले दोषी लोक सेवक को कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

★ क्या कोई माता-पिता अपने ही बच्चों के अपहरण का दोषी बन सकता है?

हिन्दुओं में सुस्थापित और प्रचलित रूढ़ी के अनुसार कोई विवाहिता नाबालिग लड़की जब तक बालिग नहीं हो जाती है, तब तक यदि वह धर्मज संतान है तो अपने पिता के संरक्षण में रहेगी और यदि वह अधर्मज संतान है तो अपनी माँ की संरक्षकता में रहेगी और यदि दोनो में से कोई एक बिना किसी दूसरे के सहमति के जिनके संरक्षकता में बच्चा है। उक्त बच्चा को ले जाता है तो वह माता या पिता व्यपहरण का अपराधी माना जायेगा और यदि किसी विवाहिता लड़की की आयु 15 वर्ष पूरी हो गई हो तो उसका विधिपूर्ण संरक्षक उसका पति होता है और यदि ऐसी कम उम्र की लड़की का पिता उसके पति के सहमति के बिना उसकी संरक्षकता में से ले जाता है तो, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अधिन व्यपहरण का अपराध किया माना जायेगा। भले ही उस पिता का आशय ऐसा करने में अपराधिक न रहा हो।

और यदि कोई स्त्री जुडिशियल सिप्रेशन के तहत अपने पति से अलग अपने बच्चे के साथ रह रही हो और ऐसी स्थिति में पिता उस बच्चे को बिना माता के सहमति के ले जाता है तो वह पिता भी अपहरण का दोषी होगा।

मुस्लिम विधि के अनुसार यदि पिता सात वर्ष से कम आयु के किसी पुत्र को अथवा कम उम्र के किसी पुत्री को यदि वह सुन्नी है अथवा सात वर्ष की कम आयु की है। यदि वह सिया है अथवा किसी अधर्मज संतान को उसकी माँ की अभिरक्षा में से ले जाता है तो उसके बारे में यह माना जा सकता है कि उसने अपने ही संतान का व्यपहरण किया है। क्योंकि माँ ही विधिपूर्ण संरक्षक मानी गई है। सुन्नी विधि के अनुसार माँ अपनी पुत्री की संरक्षिका तब तक रहती है, जब तक की वह पुत्री 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेती है।

शुद्ध चावल एवं मक्के के आटे से निर्मित नमकीन

Dhunky NAMKEEN

Shree Shyamji Udyog

गजब स्वाद की ! गजब कहानी !

fssai

Lic No. 10424110000004

Veg Biryani
masala pola
katori chaat
rings
snacks

Expanding our Namkeen family!
Dealers inquiries welcome, contact us today!

NEAR JAI PRAKASH EVENING INTER COLLEGE
JANDAHA ROAD HAJIPUR (VAISHALI)
MOB: 7782053204

MADE IN INDIA

PURE vegetarian

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008